सोशल मीडिया से जुड़ें
Parivehan_Vishesh

RNI No :- DELHIN/2023/86499
DCP Licensing Number :
F.2 (P-2) Press/2023

www.newsparivahan.com

परिवहन विशेष

वर्ष 02, अंक 31, नई दिल्ली । शनिवार, 13 अप्रैल 2024, मूल्य ₹ 5, पेज 8

देश का पहला ट्रांसपोर्ट दैनिक समाचार पत्र

आज का सुविचार

अपने छोटे-छोटे कामों में भी अपने दिल ,दिमाग और आत्मा को लगा दीजिए, यही सफलता का रहस्य है ।

03 'सीएम केजरीवाल को जेल भेजना भाजपा को पड़ेगा मंहगा'
06 विपक्षी गठबंधन और कांग्रेस की प्रासंगिकता
08 अयोध्या में विदेशी कोरोना का खतरा !, हाई अलर्ट पर प्रशासन

परिवहन विशेष द्वारा चलाए जा रहे अभियान : सड़क सुरक्षा, जाम मुक्त सड़के, हादसे मुक्त सड़के, महिला सुरक्षा, प्रदुषण नियंत्रण और आपदा निवारण सेवा के लिए

परिवहन विशेष हिन्दी दैनिक समाचार पत्र के साथ सहयोगी कुछ संस्थाओं का संक्षिप्त परिचय जाने और अन्य सहयोगी संस्थाओ का परिचय कल के प्रकाशन में

टोलवा : ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स एंड लेबर वेलफेयर एसोसिएशन (पंजीकृत)

वर्ष 1995 में स्माल दिल्ली ऑपरेटर्स फोरम के नाम से दिल्ली में हल्के वाहन मालिकों और चालकों के हित में बनाया गया था और तभी से दिल्ली में वाहन चालकों और मालिको को सड़क सुरक्षा और नियमानुसार वाहनों को दिल्ली की सड़को पर चलने की प्रेरणा देता रहा है और उनके हक के लिए दिल्ली सरकार, परिवहन विभाग और न्यायालय में अपना पक्ष रख कर उन्हे इंसाफ दिलवाने में कामयाब रहा है। वर्ष 2004 में सब्जी सदस्यों की सहमति से इसी फोरम का नाम बदल कर ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स एंड लेबर वेलफेयर एसोसिएशन रखा गया और दिल्ली में सेक्शन 1860 में इसे पंजीकृत करवाया गया था। वर्ष 2004 से यह एसोसिएशन चालको और मालिको के साथ मिलकर उनकी समस्याओं के समाधान के लिए कार्यरत हैं। इस एसोसिएशन द्वारा दिल्ली के कई चौराहों और सड़को को जाम मुक्त करवाने के दायित्व को निभाया है। इस एसोसिएशन द्वारा ही दिल्ली उच्च न्यायालय को यह बताया गया था कैसे स्पीड गवर्नर के नाम से फिल्मी

स्टाइल से परिवहन विभाग द्वारा कई वाहन मालिकों के परमिट रद्द किए गए हैं जिसका पूर्ण ब्योरा उच्च न्यायालय के आदेश में उपलब्ध है, इसी एसोसिएशन द्वारा ही दिल्ली उच्च न्यायालय को यह भी बताया गया था की वाहन के जांच प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए जांच के समय वाहन मालिकों को स्पीड गवर्नर वाली कंपनियों से अपने वाहनों की स्पीड सड़को पर चलने के आदेश से भी कम करवानी पड़ती है। दिल्ली उच्च न्यायालय को बस स्टैंड और टाइम टेबल के कारण सड़को पर होने वाली परेशानियों को अवगत करवाने का श्रेय भी इसी एसोसिएशन को है और इन सभी पर उच्च न्यायालय से वाहन मालिकों और चालकों के पक्ष मे आदेश करवाने का श्रेय भी इसी एसोसिएशन का है। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय में दिल्ली में आटो पर लगे 50000 के कैब को क्यो ना खत्म कर दिया जाए के लिए ए.पी.सी.ओ. को निर्देश दिलवाने का श्रेय भी इसी एसोसिएशन के नाम है। इस एसोसिएशन द्वारा दिल्ली में सार्वजनिक सवारी सेवा में सुधार, वाहनों में महिला सुरक्षा , जाम मुक्त और दुर्घटना मुक्त सड़को जैसे मुद्दों पर सदेव सरकार और विभाग के साथ कंधे से कन्धा मिलाकर कार्य किया है।

सड़क सुरक्षा के कार्यों के लिए 2009 से 2015 तक रोड सेफ्टी ऑफिसर के रूप कार्य किया उसके बाद रोड सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन फरीदाबाद को बनाया 2017 में इस संस्था का नाम रोड सेफ्टी ओमनी फाउंडेशन किया गया रोड सेफ्टी ओमनी फाउंडेशन 2017 में रजिस्टर्ड की गई इस संस्था को बनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों को जागरूक करना है और इसका मिशन विज़न लोगों की सेवा करना है यह संस्था नीति आयोग से रजिस्टर्ड है हरियाणा सरकार से रजिस्टर्ड है यह संस्था सड़क सुरक्षा के लिए साइबर सेल के लिए स्वच्छ भारत के लिए रेल सुरक्षा, ब्लड डोनेशन के लिए लिए एवं जल बचाओ, बिजली बचाओ के लिए एवं अन्य सामाजिक कार्यों के लिए दिन रात कार्य करती है। कॉविड-19 में दिन रात लोगो को खाना, दवाई बाटने का कार्य किया। मोटर व्हीकल एक्ट 2019 और सड़क सुरक्षा के प्रति पिछले 5 साल से स्कूल कॉलेज बस अड्डा रेलवे स्टेशन मेट्रो स्टेशन इंडस्ट्रीज एरिया में जा जाकर लोगों को जागरूक किया। साइकिल पर हेलमेट के ऊपर एवं अन्य साधनों पर रिफ्लेक्टर टेप लगाई गई इस कार्य को दिन-रात किया बिना रुके बिना डरे इसके लिए हमारी पूरी टीम बधाई की पात्र है जो बिना किसी लालच के कार्य करती है और दिन रात करती है रोड सेफ्टी ओमनी फाउंडेशन के पूरे परिवार को बहुत-बहुत बधाई **संस्था को हरियाणा के चीफ मिनिस्टर ने हरियाणा के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने भारत सरकार के मंत्रियों एवं जिला प्रशासन ने हमारी संस्था को अनगिनत बार सम्मानित किया है।** दिल्ली पुलिस ने भी हमारी संस्था को सम्मानित किया है हमने हरियाणा पंजाब दिल्ली नोएडा झारखंड में भी सड़क सुरक्षा पर कार्य किया है और निरंतर कर रहे हैं। हमारी संस्था को हरियाणा प्रदेश के सभी अधिकारियों ने बधाई दी है एवं आगे से और अच्छा कार्य करने की प्रेरणा दी है आप आगे बढ़ो हम आपके साथ-साथ हैं। **हमारी संस्था जिला विधिक सेवा प्राधिकरण फरीदाबाद पलवल मेवात के साथ भी जगह-जगह पर जागरूक कैंप लगाती है** आदरणीय चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट मंगलेश कुमार चौबे जी ने भी हमें बधाई दी है और आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है।

दिल्ली परिवहन विभाग के आला अधिकारी के जागने से पहले दिल्ली एनसीआर में नही हो सकता सुधार: टोलवा

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। जी हां, आपकों यह बात अटपटी लग रही होगी पर यह सच है, दिल्ली भारत देश की राजधानी जहां हर पल हर कण हर क्षण सुरक्षा की सबसे ज्यादा आवश्यकता है वहा दिल्ली परिवहन विभाग एसटीए सचिव उर्फ विशेष आयुक्त प्रवर्तन शाखा उर्फ विशेष आयुक्त वाहन जांच शाखा ऊर्फ विशेष आयुक्त आटो टेक्सी शाखा उर्फ विशेष आयुक्त स्क्रैप शाखा ऊर्फ विशेष आयुक्त ऑपरेशन उर्फ विशेष आयुक्त एडमिन उर्फ विशेष आयुक्त प्रदूषण शाखा एवम् अन्य कई शाखाओं के विशेष आयुक्त होने के साथ विशेष परिवहन आयुक्त दिल्ली के पद पर विराजमान होकर जो दिशा निर्देश परिवहन विभाग में उनके अंतर्गत आने वाली शाखाओं के अधिकारियों और कर्मचारियों को जारी करेंगे इसी के आधार पर ही दिल्ली और दिल्ली एनसीआर में वाहन सेवा नजर आएगी। **किसी भी राज्य में सचिव एसटीए का मुख्य दायित्व है उस राज्य की जनता को सुदृढ़, सुरक्षित, विश्वसनीय और समय सीमा में सार्वजनिक सवारी सेवा उपलब्ध करवाना** लेकिन दिल्ली का सौभाग्य है की सचिव एसटीए के पास हर अन्य कार्य के लिए भरपुर समय है पर सबसे ज्यादा जरूरी दायित्व के प्रति एक सेकंड का भी समय उपलब्ध नही है। अब आप सभी विशेषज्ञ अपने नजरिए/ सोच का प्रयोग कर बताए **'जब सार्वजनिक सवारी सेवा उपलब्ध नहीं होगी'** तब जनता के पास निजी नम्बर वाहनों, बाहरी राज्यों के पंजीकृत वाहनों, बिना फिटनेस वाले वाहनों, बिना इंश्योरेंस वाले वाहनों, बिना वैध लाइसेंस धारक द्वारा चलाए जाने वाले वाहनों को देखना जरूरी होगा या किसी भी हालात में अपने गंतव्य स्थान पर समय पर पहुंचना ? हमारा यह दुर्भाग्य है कि भारत देश में जो नियम/ कानून/ धारा/ अधिनियम बनाए वा लागू किए जाते हैं वह

सामान्य भोली भाली जनता के लिए होते हैं ना की दबंगों के लिए और ना ही उन सरकारी अधिकारियों, सरकारी विभागो की लिए जो अपने हिस्सा का कार्य नही करते। हा जब कभी इस तरह का कोई हादसा हो जाए तो दिखाने के लिए सिर्फ छोटी गलती वाले वाहन मालिको के वाहन बंद कर अपनी कागजी कार्रवाई दिखा देते हैं यह सरकारी अधिकारी और कर्मचारी, आज पूरे हरियाणा, उत्तर प्रदेश में वाहनों की जांच बड़ी सरगर्मी से की जा रही है पर फिर भी आप सड़को पर, राजमार्गो पर और राज्य एवम जिला क्षेत्र में गैर कानूनी तरीके से चलने वाले वाहनों को बेखौफ चलते देख सकते है क्योंकि यह जांच उनके लिए नही सिर्फ खाना पूर्ति के प्रति है। जब तक दिल्ली में गैर कानूनी तरीके से आने- जाने और चलने वाले वाहनों पर दिल्ली परिवहन विभाग पाबन्दी नही लगवाएगा तब तक दिल्ली एनसीआर की जनता प्रदुषण, जाम और दुर्घटनाओ का दौर देखती ही रहेगी। **आप और हम कितनी भी मेहनत कर ले जब तक प्रशासनिक अधिकारी नही जागेगा और अपना दायित्व सही ढंग से नहीं निभाएगा तब तक सब ऐसे ही रहेगा।** इसलिए अगर **सुरक्षित सवारी सेवा के साथ जाम मुक्त और दुर्घटना मुक्त सड़को की आशा करते हो तो वाहन चालकों को नही दिल्ली एनसीआर में कार्यरत प्रशासनिक अधिकारियों को जगाने में समय लगाओ।**

संजय बाटला (अध्यक्ष टोलवा)

दिल्ली परिवहन विभाग की शाखाओं द्वारा नाम में बदलाव करवाने वालों को किया जा रहा है परेशान...

संजय बाटला

नई दिल्ली। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा विधि विधान से पारित गैजेट नोटिफिकेशन होने के बाद भी दिल्ली परिवहन विभाग की शाखाओं में अपने लाइसेंस/ आरसी में नाम बदलवाने वालो को किया जा रहा है परेशान और आला अधिकारी है चुप, आख़िर क्यों ? जानकारी प्राप्त करने पर पाया गया 90 % नाम बदलवाने वाले व्यक्तियों द्वारा लाइसेंस बनवाने के समय जो दस्तावेज़ प्रस्तुत किए गए थे उन्हें लाइसेंस में वही नाम चाहिए पर किस आधार पर परिवहन विभाग ने बिना किसी कागजात के उसकी जगह दूसरा नाम प्रिंट कर दिया इसको बताने की जगह दोषी लाइसेंस धारक को बता कर लाइसेंस में नाम नही बदल कर दे रहे, कुछ नाम परिवर्तन करवाने वाले सबूत मे अपना पासपोर्ट, आधार कार्ड, पैन कार्ड प्रस्तुत कर लाइसेंस में नाम बदलवाना चाहते हैं पर दिल्ली परिवहन के अधिकारी उसे भी करने को तैयार नहीं, आख़िर क्यों ? आपकी जानकारी हेतु बता दें नाम परिवर्तन में किसी को अपना कास्ट लिखवानी है या लिखी हुई कास्ट को हटवाना है वह भी अपनें अन्य दस्तावेज़ के अनुसार जहा यह साफ है की इसमें कोई गलती नहीं करवाई जा रही है पर 'दिल्ली परिवहन विभाग की शाखाओं में कार्यरत अधिकारी' भी परिवहन विभाग के आला अधिकारी की तरह अपनी सोच को नियम और कानून मानते हैं और करते हैं परेशान दिल्ली की जनता को ! अब आप बताए कहा जाए यह बिना वजह और परिवहन विभाग के ही किसी अधिकारी की गलती की सजा भुगतते परेशान नागरिक ?

चार्जिंग के दौरान E स्कूटी की बैटरी ब्लास्ट, गंभीर रूप से झूलसी युवती, इलाज के दौरान

परिवहन विशेष नयूज

नई दिल्ली। किराए के मकान में रह रही एक युवती 26 मार्च मंगलवार की रात इलेक्ट्रिक स्कूटी की बैटरी चार्ज कर रही थी। इसी दौरान तेज धमाके के साथ बैटरी फट गया और युवती गंभीर रूप से झुलस गई। उसे तत्काल सूरजपुर अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसकी गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे उपचार हेतु अंबिकापुर अस्पताल रेफर कर दिया। फिर अंबिकापुर से उसे रायपुर रेफर कर दिया गया, जहां आज इलाज के दौरान युवती की मौत हो गई है। मिली जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत कुरुवा आमापारा निवासी 23 वर्षीय पार्वती सिंह पिता स्व. हरि प्रसाद पिछले 8-9 महीने से सूरजपुर के चंद्रपुर में एक किराए के मकान में अपनी बड़ी बहन सावित्री सिंह के साथ रहती है। वह नेटवर्क मार्केटिंग में फील्ड ऑफिसर के पद पर काम करती है। बता दें कि 26 मार्च मंगलवार की रात करीब 9 बजे वह अपनी इलेक्ट्रिक स्कूटी (Electric scooty) की बैटरी को वाहन से निकालकर कमरे में लाकर चार्ज कर रही थी। इसी दौरान अचानक चार्जिंग के दौरान बैटरी फट गई, जिससे युवती गंभीर रूप से झुलस गई थी। जो 26 दिनों तक रायपुर के अस्पताल में जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही थी। कोतवाली पुलिस जांच में जुटी हुई है।

बाल सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देना: सड़क सुरक्षा ओमनी फाउंडेशन द्वारा एक सहयोगात्मक पहल

सामुदायिक सहयोग के उत्साहजनक प्रदर्शन में, रोड सेफ्टी ओमनी फाउंडेशन, eco club ने बाल सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक जीवंत रैली का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में स्कूली बच्चों की उत्साहपूर्ण भागीदारी देखी गई, जिन्हें यातायात अधिकारियों द्वारा हेलमेट पहनने के महत्व के बारे में जागरूक किया गया।

रैली के दौरान एक महत्वपूर्ण क्षण प्रसिद्ध 'हेलमेट मैन ऑफ इंडिया' राघवेंद्र कुमार द्वारा रंगीन हेलमेट का वितरण था, जो बच्चों को हेलमेट उपयोग को प्राथमिकता देने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए एक ठोस प्रयास की शुरुआत का प्रतीक था।

यह पहल मोटर वाहन अधिनियम द्वारा निर्धारित नए नियमों के अनुरूप है, जो दोपहिया वाहनों पर पीछे की सीट पर सवारी करने वाले बच्चों के लिए क्रैश हेलमेट और सुरक्षा हार्नेस का उपयोग अनिवार्य करता है। ये नियम सड़कों पर युवा जीवन की सुरक्षा की प्रतिबद्धता को रेखांकित करते हैं।

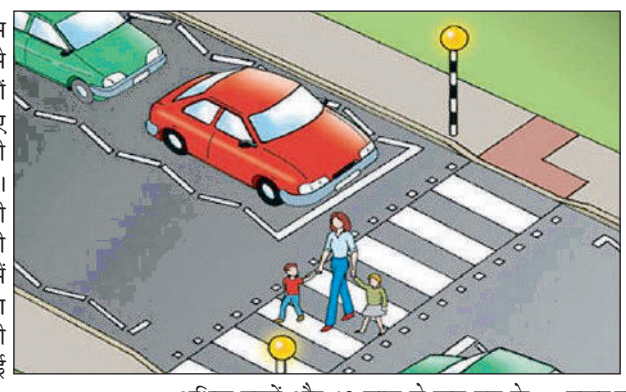

मोटर वाहन अधिनियम की धारा 129 चार साल से अधिक उम्र के बाइक सवारों और पीछे बैठे यात्रियों के लिए सुरक्षात्मक टोपी की आवश्यकता पर जोर देती है। हेलमेट की मोटाई, फोम की गुणवत्ता और वजन की सीमाओं के संबंध में विशिष्टताओं की रूपरेखा तैयार की गई है, जिसमें सभी हेलमेटों पर आईएसआई चिह्न होना आवश्यक है।

इसके अलावा, केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 में हालिया संशोधन, नौ महीने से चार साल की उम्र के बच्चों के लिए अनिवार्य सुरक्षा हार्नेस और हेलमेट पेश करता है। ऐसे वाहनों के लिए 40 किमी प्रति घंटे की गति प्रतिबंध का उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं से जुड़े जोखिमों को कम करना है।

2020 में 14 साल से कम उम्र के 2,700 से अधिक बच्चों और 18 साल से कम उम्र के 14,000 बच्चों की सड़क दुर्घटनाओं में मौत के साथ, सक्रिय उपायों की आवश्यकता को कम करके आंका नहीं जा सकता है। हार्नेस, बाल हेलमेट और गति सीमा का कार्यान्वयन बाल सड़क सुरक्षा को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतीक है।

सड़क सुरक्षा ओमनी फाउंडेशन, परिवहन विशेष और हेलमेट मैन ऑफ इंडिया के सहयोग से, जागरूकता अभियान और स्कूल पहल सहित निरंतर वकालत प्रयासों के लिए प्रतिबद्ध है। ब्रांड एंबेसडर के रूप में आद्या शरण (कुहू) की नियुक्ति बच्चों के बीच हेलमेट के उपयोग के संदेश को और बढ़ाती है।

जैसा कि हम इस मुद्दे का समर्थन करते हैं, आइए याद रखें कि अनुकरणीय नेतृत्व सही उदाहरण स्थापित करने से शुरू होता है। आइए हम सड़क सुरक्षा को प्राथमिकता देने का संकल्प लें, यह मानते हुए कि राजा मुकुट पहनते हैं, लेकिन दिग्गज हेलमेट पहनते हैं। साथ मिलकर, हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि सड़क दुर्घटनाओं में किसी की जान न जाए, जिससे सड़क सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता बन जाए।

डॉ. अंकुर शरण
नेशनल चीफ प्लानिंग एंड ट्रांसपोर्ट ऑफिसर
रोड सेफ्टी ओमनी फाउंडेशन (रजि.)

हरियाणा में हुए हादसे से यूपी जागा पर कब जागेगा दिल्ली परिवहन विभाग ? टोलवा

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। हरियाणा में हुए स्कूल बस हादसे के बाद **हरियाणा सरकार द्वारा कार्यवाही के साथ ही उत्तर प्रदेश ने भी उठाए सख्त कदम, पर दिल्ली के परिवहन विभाग के आला अधिकारी की कब खुलेगी आंख ?** योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में सरकारी स्कूलों की स्थिति को बदलने के लिए पिछले कुछ सालों में कई बड़े कदम उठाए गए हैं। स्कूल में छात्रों को बेहतर शिक्षा मुहैया कराने के साथ, उन्हें ड्रेस, किताब, मिड मील जैसी सुविधाएं पहले से ही मिल रही है लेकिन अब स्कूलों में छात्रों की सुरक्षा को लेकर सरकार की ओर से बड़ा कदम उठाया गया है। सरकार की ओर से बच्चों की सुरक्षा के लिए मिशन भरोसा की शुरुआत की गई है। यह पोर्टल और मोबाइल एप्लिकेशन है। छात्रों को स्कूल लाने और घर जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन के दौरान उनकी सुरक्षा काफी अहम है, जिसपर सरकार की ओर से विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इस मुहिम के जरिए सरकार वैन ड्राइवर्स का पुलिस वेरिफिकेशन कराती है। साथ ही वैन में अटेंडेंट का भी वेरिफिकेशन कराया जाना अनिवार्य किया गया है। ताकि छात्रों को उनके घर से स्कूल सुरक्षित पहुंचाया जा सके। किसी भी तरह का वाहन फिर वह बस हो, ऑटो रिक्शा हो या फिर ई-रिक्शा सभी को इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है अगर उन्हें स्कूली बच्चों को लाना और ले जाना है। इस ऐप पर रजिस्ट्रेशन कराने के साथ जरूरी दस्तावेजों को अपलोड करना अनिवार्य है। इसके साथ ही जिस वाहन का इस्तेमाल स्कूल से बच्चों को लाने ले जाने के लिए हो रहा है उसका आरटीओ रजिस्ट्रेशन होना भी अनिवार्य है। मिशन भरोसा की तारीफ करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथने कहा था इस ऐप के जरिए आरटीओ, पुलिस, शिक्षा विभाग, गाड़ी मालिक, अभिभावक, आम नागरिकों के बीच बेहतर संवाद स्थापित हो पाता है। इस ऐप और तकनीक के जरिए छात्रों को सुरक्षित वाहन और ट्रांसपोर्ट की सुविधा मिलेगी। योगी सरकार इस ऐप के जरिए छात्रों की सुरक्षा को लेकर अपनी प्रतिबद्धता को जाहिर करती है। यह ऐप स्कूली छात्रों के लिए सुरक्षा का काम करेगा और उन्हें सुरक्षित ट्रांसपोर्ट सुनिश्चित करेगा। बच्चों की सुरक्षा के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ ना हो इसे सरकार इस ऐप के जरिए सुनिश्चित कर रही है। अहम बात यह है कि इस मिशन के जरिए स्कूली वाहन के ड्राइवर और अटेंडेंट को भी अवेयरनेस प्रोग्राम के तहत ट्रेनिंग दी जाएगी। ड्राइवर और अटेंडेंट को बच्चों से जुड़ी सुरक्षा के प्रोटोकॉल, रेग्युलेशन हेल्थ और अन्य चीजों की ट्रेनिंग दी जाएगी। यही नहीं इस ऐप पर अभिभावक, स्कूल के शिक्षक भी अपने सुझाव और फीडबैक दे सकते हैं। इस ऐप पर जो भी सुझाव दिए जाएंगे उसे लागू किया जाएगा।

राष्ट्र नायक डॉ बाबा साहेब की 134वीं जयंती विशेष : आइए इस 14 अप्रैल पर डॉ बाबा साहेब के सम्मान में अपने घर और कार्यस्थल पर दीप जलाएं

वरिष्ठ समाजसेवी मुशरफ खान

डॉ. बाबा साहेब की जयंती को ज्ञान दिवस के रूप में मनाएं : वरिष्ठ समाजसेवी मुसरफ खान

डॉ. बाबा साहेब के योगदान को कभी भी नहीं भुलाया जा सकता, हम हमेशा उनके क़र्ज़दार रहेंगे : वरिष्ठ समाजसेवी मुसरफ खान

भारतीय समाज में राष्ट्र नायक डॉ बाबा साहेब भीमराव रामजी अम्बेडकर जी के अपार योगदान और समानता और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने में उनकी स्थायी विरासत को मान्यता देते हुए, इस दिन को पूरे भारत में उनकी विरासत का सम्मान करने के लिए बहुत सम्मान से हर्षोल्लास और उत्साह के साथ मनाया जाता है।

राष्ट्र नायक डॉ बाबा साहेब भीमराय रामजी अम्बेडकर जी के 134वे जन्म दिवस के शुभ अवसर पर सभी देशवासियों को शुभकामनायें व्यक्त करते हुए सुप्रशिद्ध एवं लोकप्रिय वरिष्ठ समाजसेवी मुसरफ खान ने कहा कि आइएं इस 14 अप्रेल पर बाबा साहेब के सम्मान में अपने घर और कार्यस्थल पर दीप जलाएं और डॉ. बाबा साहेब की जयंती को ज्ञान दिवस के रूप में मनाएं। हम हमेशा डॉ बाबा साहेब के क़र्ज़दार रहेंगे क्योकि उनके चिंतन और विचारों में देश सबसे ऊपर हैं। बाबा साहेब के विचारों से आप स्वयं का निर्माण कर परिवार, समाज एवं राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि भारत को समझना, भारत को मनाना, भारत के बनो और भारत को बनाओं के मंत्र से ही सशक्त एवं विकसित राष्ट्र का निर्माण होगा। इसलिए सभी को बाबा साहेब की तरह अच्छी शिक्षा लेनी चाहिए परंतु अच्छी शिक्षा के साथ ही हमारा प्रथम उद्देश्य राष्ट्रहित भी होना चाहिए। किसी का भी जीवन तभी अच्छा बनता है, जब उनका जीवन जीवनमूल्यों से युक्त होता है। हमें अपना व्यक्तित्व अच्छा बनकर चरित्रवान एवं बुद्धिमान बना है। युवाओं की सोच एवं उनकी ऊर्जा में वह शक्ति होती है जो असंभव को भी संभव कर देती है। इसलिए हमें राष्ट्रहित के लिए छोटे- छोटे पहलुओं पर ध्यान देना होगा और युवाओं और समाज को को जागरूक करना होगा। यही बाबा साहब की सोच और शिक्षा थी, लेकिन हमारे देश के अंदर हजारों सालों से अभी कुछ जगह व्याप्त जातिवाद एवं क्षेत्रवाद जैसे गंभीर मुद्दे युवाओं और समाज के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। आज इस तेजी से परिवर्तन के दौर में युवा और सम्पूर्ण समाज को इन चुनौतियों को स्वीकार कर इन्हें समाजवाद से जोड़कर राष्ट्रहित में जुड़ जाना चाहिए। जैसे ग़रीबी की कीचड़ में जेड होने के बावजूद 'बाबा साहेब कमल' की तरह खिलकर पुरे देश के वातावरण को महकता है। उसी तरह हमें भी अपना ऐसा व्यक्तित्व निर्माण करना चाहिए, जिससे संपूर्ण समाज को महकते हुए हम राष्ट्र निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें सके। देश के लिए किये गए डॉ. बाबा साहेब के योगदान को कभी भी नहीं भुलाया जा सकता, हम हमेशा उनके क़र्ज़दार रहेंगे। उन्होंने कहा यह पर्व आपसी भाईचारे एवं एकता का प्रतिक हैं। डॉ बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी ने भारत का संविधान लिखकर हम सब को समान अधिकार दिया हैं। डॉ बाबा साहेब ने अपने लिखें संविधान में हमें वोट डालने का अधिकार दिया हैं। नारी शक्ति को भी सम्मान देते हुए बराबरी का हक दिया हैं। उन्होंने भारत के प्रत्येक नागरिक को हर प्रकार की आज़ादी, मूलभूत सुविधाएं संविधान में प्रदान की गयी हैं। इसलिए हमारा कर्तव्य बनता हैं कि हम सब डॉ बाबा साहेब द्वारा दिये गए दिशा निर्देशों पर पूरी ईमानदारी से चलें और उनके द्वारा बताएं गए कर्तव्यों का निष्ठां से पालन करें। आपसी भाईचारे एवं एकता के पर्व पर मैं मुसरफ खान बाबा साहेब डॉ भीमराव अंबेडकर जी को उनकी 134वी जन्म जयंती के शुभ अवसर पर कोटी-कोटी नमन करते हुए उन्हें बारम्बार श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उन्होंने कहा कि डॉ बाबा साहेब की जन्म जयंती पर, हम भारत के लोगों की तरफ से अपनी सामूहिक शक्ति का ये प्रदर्शन, ये संकल्प राष्ट्र नायक, भारतीय सविधान के रचयिता, भारत गणराज्य के निर्माता, कानून और अर्थशास्त्र के विशेषज्ञ, देश के प्रथम विधि एवं न्याय मंत्री, दलित, शोषित पीड़ित वंचितो के मसीहा, सामाजिक न्याय के प्रणेता, देश को नई दिशा देने वाले, गरीब के ग्रेट लीडर डॉ बाबा साहेब की 134वी जन्म जयंती पर सच्ची श्रद्धांजलि है।

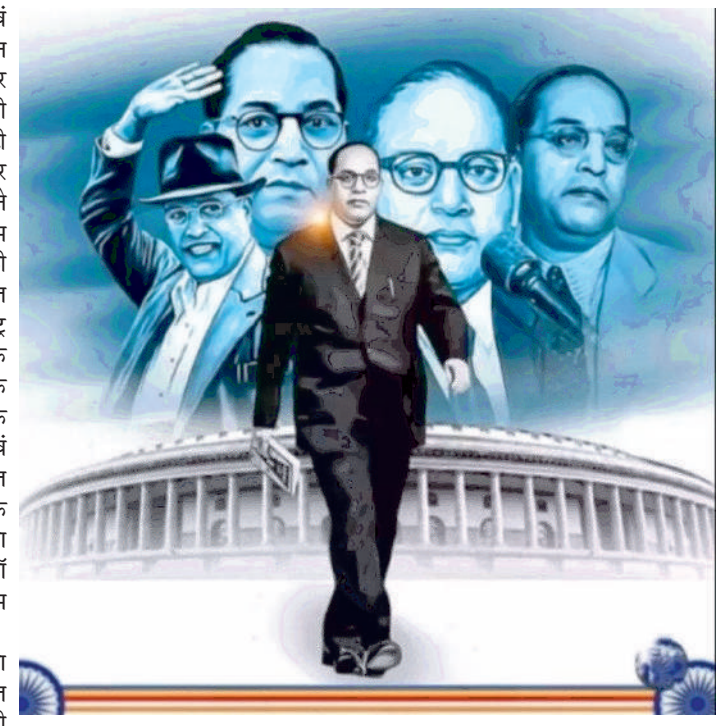

उन्होंने कहा कि डॉ बाबा साहेब के विचारों पर आधारित किताबें स्वयं पढ़े और बच्चों को भी बांटे तथा सभी से किताबें पढ़ने की अपील करें ताकि डॉ बाबा साहेब के राष्ट्रवादी विचारों का घर - घर में प्रसार हो और ये महत्वपूर्ण सन्देश देश विदेश और प्रदेश भर में बड़े स्तर जाये। जिससे पीढ़ियों को एक समावेशी और न्यायसंगत समाज की दिशा में अपना काम जारी रखने के लिए प्रेरणा मिलती है। डॉ अम्बेडकर जी का दर्शन आज भी वर्तमान समाज के लिए प्रासंगिक है। भारत की सामाजिक - सांस्कृतिक व्यवस्था को आकार देने में उनकी सक्रिय भूमिका के बिना, पुरातन मान्यताओं वाले देश से दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र वाले देश बनने में कोई प्रगति करना असंभव होता। हमारे संविधान ने अधिक न्यायापूर्ण और लोकतान्त्रिक समाज बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण और लंबे कदम बढ़ाये हैं, लेकिन स्वतंत्रता के समय हमारे समाज में गहरी जड़े जमाई हुई आज़ादी के 76सालों के बाद भी असमानता आज़ भी मौजूद हैं। अभी इस पर एकता और राष्ट्रहित में काफ़ी कार्य किया पूरा किया जाना शेष हैं और सामाजिक असमानता को दूर करने के लिए हमारे सर्व समाज में एकता और संविधानवाद की भावना लाने की ज़रूरत हैं। यादि क़ानून के युवा छात्रों और सनातकों का मार्गदर्शन संविधान के मूल्यों से होगा, तव वे नाकाम नहीं होंगे। इस विचार का विस्तार है कि न्यायालय से संपर्क करने का अधिकार संविधान का हृदय और आत्मा है।संविधान अस्तित्व में है और संविधान काम करता है। डॉ बाबा साहेब ने हमारे देश का संविधान लिखा जिसके तहत हमारी सरकारे बर्षो वर्ष से सुचारु रूप से चल रही हैं। भारत के लोग कई संवेधानिक अधिकारों के लिए डॉ बाबा साहेब भीमराय अम्बेडकर जी के क़र्ज़दार हैं। बाबा साहेब ने भारत के औपनिवेशक शासकों के अनुग्रह के रूप में हमें संविधान नहीं प्रदान किया हैं। हमारा संविधान एक ऐसा दस्तावेज हैं जिसे देश में ही तैयार किया गया हैं, जो स्वशासन, गरिमा और स्वतन्त्रता का उत्पाद हैं। हमारा संविधान जीवन का माध्यम है।

उन्होंने कहा कि डॉ अंबेडकर जी ने अपना सारा काम और जीवन दबे - कुचले गरीबों, मजदूरों, महिलाओं और अछूतों के उत्थान के लिए समर्पित कर दिया। डॉ. बीआर अंबेडकर जी ने न केवल देश को अपना संविधान दिया बल्कि भारत की केंद्रीय बैंकिंग संस्था, भारतीय रिजर्व बैंक के गठन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के रूप में जाना जाता है, बनाने में उनका योगदान बहुत बड़ा था।आज भी भारत और दुनिया भर में युवा पीढ़ी के मन को प्रेरित करते हैं। एक अर्थशास्त्री होने के नाते उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था को समझने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने लाखों लोगों को औद्योगिक और कृषि गतिविधियों के विकास के लिए प्रेरित किया। वह भारत के महानतम लोगों में से एक थे जिन्होंने लोगों को बेहतर सामुदायिक स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए प्रेरित किया। डॉ. अम्बेडकर जी के जन्मदिन पर भारत के सबसे महान दिमागों में से एक को सम्मान देने से बेहतर कुछ नहीं है। देश के विकास के लिए हम सब भारतीयों को आपस में मिलजुल कर देश को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करना चाहिए। आज हम सब की जिम्मेदारी है कि हम एक दूसरे की मदद करें और देश को उन्नति एवं विकास के पथ पर आगे बढ़ाएं क्योकि डॉ बाबा साहब ने अपना पूरा जीवन गरीबों, कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए न्योछावर कर दिया। बाबा साहब ने समाज में हर वर्ग को समानता दिलाने के लिए जीवन भर कठिन संघर्ष किया। बाबा साहेब का संघर्ष सम्पूर्ण विश्व के लोगों के लिए एक मिसाल हैं। हम कभी भी बाबा साहब के त्याग और बलिदान को भुला नहीं सकते। हम सब भी उनके विचारों और क़तिाबों को पढ़कर काबिल इंसान बन सकते हैं। राष्ट्र की तरक़्क़ी हेतु हमें डॉ बाबा साहब के राष्ट्रीवादी सामाजिक चिंतन एवं हर भारतीय के लिए राष्ट्र प्रथम जैसे महत्वपूर्ण विचारों की बहुत आवश्यकता हैं। आज हमें राष्ट्रहित में देश की तरक्की, उन्नति, विकास और आपसी एकता के लिए सामाजिक असमानता को दूर कर एक साथ मिकलर सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ना चाहिए और देश की उन्नति के लिए शिक्षा हर भारतीय के जीवन का महत्वपूर्ण आधार होना चाहिए।

भारत की प्राकृतिक विरासत का संरक्षण: विरासत वृक्षों की रक्षा के लिए महाराष्ट्र की पहल: डॉ. अंकुर शरण

पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक प्रगतिशील कदम में, महाराष्ट्र सरकार ने विरासत के खजाने माने जाने वाले पेड़ों की सुरक्षा के लिए एक व्यापक योजना का अनावरण किया है। महाराष्ट्र (शहरी क्षेत्र) वृक्ष संरक्षण और संरक्षण अधिनियम 1975 में प्रस्तावित संशोधन के तहत, 50 वर्ष या उससे अधिक की अनुमानित आयु वाले पेड़ों को विरासत वृक्ष के रूप में मान्यता दी जाएगी। यह महत्वपूर्ण कदम अपनी प्राकृतिक विरासत को संरक्षित करने और सतत शहरी विकास को बढ़ावा देने के लिए राज्य की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।

विरासत वृक्षों की अवधारणा महज उम्र से परे है; इसमें आकार, आकार, दुर्लभता और ऐतिहासिक महत्व जैसे विभिन्न मानदंड शामिल हैं। ये पेड़ समय बीतने के जीवित गवाह के रूप में काम करते हैं, इतिहास, संस्कृति और जैव विविधता की समृद्ध टेपेस्ट्री के गवाह हैं। चाहे वे ऐतिहासिक शख्सियतों, स्थलों या मिथकों से जुड़े हों, विरासत के पेड़ अपने परिवेश की पहचान और चरित्र को आकार देने में अत्यधिक महत्व रखते हैं।

महाराष्ट्र की पहल की विशिष्ट विशेषताओं में से एक सामुदायिक भागीदारी और सार्वजनिक भागीदारी पर जोर देना है। वन विभाग ने अपने प्राकृतिक पर्यावरण के प्रति लोगों के बीच स्वामित्व और जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देने के लिए, अपने आसपास के क्षेत्र में संभावित विरासत पेड़ों की पहचान करने के लिए नागरिकों से प्रस्ताव आमंत्रित किए हैं। यह सहयोगात्मक दृष्टिकोण सुनिश्चित करता है कि संरक्षण प्रयासों में स्थानीय ज्ञान और विशेषज्ञता का लाभ उठाया

जाता है, जिससे अधिक समावेशी और प्रभावी परिणाम प्राप्त होते हैं।

इसके अलावा, प्रस्तावित कार्य योजना में विकास गतिविधियों के कारण पेड़ों के नुकसान की भरपाई के लिए क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के प्रावधान शामिल हैं। काटे गए प्रत्येक पेड़ के लिए, बराबर संख्या में पौधे लगाए जाएंगे, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि पारिस्थितिक संतुलन बना रहे। इन पौधों को जियो-टैगिंग से गुजरना होगा और सात साल तक देखभाल मिलेगी, जिससे उनका अस्तित्व और स्वस्थ, परिपक्व पेड़ों के रूप में विकास सुनिश्चित होगा।

स्थानीय स्तर पर महाराष्ट्र वृक्ष प्राधिकरण का गठन योजना का एक अन्य प्रमुख घटक है। इस प्राधिकरण को वृक्ष संरक्षण प्रयासों की निगरानी करने और अपने-अपने क्षेत्रों में पेड़ों की सुरक्षा के संबंध में निर्णय लेने का काम सौंपा जाएगा। निर्णय लेने की प्रक्रिया को विकेंद्रीकृत करके और स्थानीय निकायों को सशक्त बनाकर, सरकार का लक्ष्य वृक्ष संरक्षण उपायों के त्वरित और कुशल कार्यान्वयन को सुनिश्चित करना है।

विरासत वृक्षों के संरक्षण के अलावा, योजना राज्य भर में वृक्षों के स्वास्थ्य और वितरण की निगरानी के लिए नियमित वृक्ष जनगणना आयोजित करने के महत्व पर भी जोर देती है। यह डेटा-संचालित दृष्टिकोण नीति निर्माण और संसाधन आवंटन के लिए मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करेगा, जिससे अधिकारियों को वृक्ष संरक्षण और शहरी नियोजन के बारे में सूचित निर्णय लेने में सक्षम बनाया जा सकेगा।

बेहतर पड़ोस के लिए साझेदारी: शहरी वातावरण में पेड़ों का महत्व

शहरी जीवन में हम सभी व्यस्त हैं, और अक्सर हम अपने पर्यावरण की ओर ध्यान नहीं देते। हमें यह याद रखना चाहिए कि हमारा आसपास का माहौल हमारे स्वास्थ्य और कल्याण पर सीधा असर डालता है। इसीलिए, बेहतर पड़ोस को बनाए रखना और अपने शहर को हरित और स्वस्थ बनाने के लिए पेड़-पौधों के रोपण को बढ़ावा देना अत्यंत महत्वपूर्ण है।

पेड़ों का रोपण करना एक महत्वपूर्ण कदम है जो हमारे पर्यावरण को सुरक्षित और स्वस्थ रखने में मदद कर सकता है। यह न केवल हमारे वातावरण को साफ और ताजगी देता है, बल्कि यह हमें शांति और सामर्थ्य भी प्रदान करता है।

पेड़ों के रोपण के फायदे अनगिनत हैं। पेड़ों की छाया हमें गर्मी से बचाती है और प्राकृतिक सुंदरता और हरियाली का आनंद देती है। इसके साथ ही, पेड़ हमारे वायुमंडल को शुद्ध करते हैं और ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, जो हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण है।

हालांकि, आजकल कई शहरों में हाई टेंशन तारों के नीचे पेड़ लगाने की प्रथा देखी जा रही है, जिससे ऐसे पेड़ों को स्थायी और उच्चायु प्राप्त करने में समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। इस प्रकार के पेड़ों का सही देखभाल न केवल हमारे पर्यावरण को नुकसान

पहुंचाता है, बल्कि यह हमारे स्वास्थ्य और कल्याण को भी प्रभावित करता है।

इसलिए, हमें सही रास्ते से अपने पेड़ों का प्रबंधन करने की जरूरत है। हाई टेंशन तारों के नीचे पेड़ लगाने से पहले, हमें पेड़ों के स्थान और उनकी ऊंचाई का ध्यान रखना चाहिए। सही तकनीक और सहायक उपकरणों का उपयोग करके, हमें पेड़ों को सही ढंग से छांटना और तैयार करना चाहिए, ताकि उन्हें सही संरक्षण और पोषण प्राप्त हो सके।

साथ ही, हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि पेड़ों को समय-समय पर सही तरीके से देखभाल और अनुदान प्रदान किया जाना चाहिए।

indiangreenbuddy@gmail.com

'मेरा घोसला.कॉम' नन्हीं कुहू की गौरैया के लिए बड़ी पहल, इकोसिस्टम पार्टनर्स के सहयोग से मिले पंख'

करुणा और पर्यावरण प्रबंधन की एक हृदयस्पर्शी कहानी में, 8 वर्षीय कुहू ने पक्षी घरों के उपयोग को बढ़ावा देकर गौरैया का समर्थन करने के मिशन पर काम शुरू किया है। एक साधारण जन्मदिन के उपहार के रूप में शुरू हुई यह मुहिम एक पूर्ण अभियान में बदल गई है, जिसमें कुहू और उनके समर्थकों ने दोस्तों और परिवार को इस मुहिम में शामिल होने के लिए एकजुट किया है।

कुहू की प्रेरणा उसके अपने जन्मदिन के उपहार - एक पक्षीघर Bird House - से उत्पन्न हुई। उन्होंने अपने प्रियजनों से पारंपरिक उपहारों के बजाय इसे सबसे अच्छा रिटर्न गिफ्ट मानते हुए गौरैया के लिए आश्रय प्रदान करने में योगदान देने की अपील की। अपने जुनून से प्रेरित और अपने परिवार और दोस्तों के समर्थन से, कुहू की पहल, जिसे उपयुक्त रूप से मेरा घोसला.कॉम नाम दिया गया है, ने कई लोगों के दिलों पर कब्जा कर लिया है।

इस जमीनी स्तर के आंदोलन को व्यापक समर्थन मिला है, जिसमें विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्र भागीदारों ने अपनी विशेषज्ञता और संसाधन उधार दिए हैं। ग्लोबल कन्फेडरेशन ऑफ एनजीओ, मानव रचना यूनिवर्सिटी, रोड सेफ्टी ओमनी फाउंडेशन, National Human Welfare Council, Geebsys.com, uneako.com, CargoInsights.co और परिवहन विशेष जैसे उल्लेखनीय संगठनों ने गौरैया संरक्षण के लिए कुहू के साथ हाथ मिलाया है।

इन साझेदारों में, टीम परिवहन विशेष और रोड सेफ्टी ओमनी फाउंडेशन इस उद्देश्य का समर्थन करने में दिग्गजों के रूप में उभरे हैं। सड़क सुरक्षा के प्रति उनका समर्पण पर्यावरण और सामाजिक कल्याण के अंतर्संबंध पर जोर देते हुए, गौरैया को भोजन और आश्रय प्रदान करने के मिशन के साथ पूरी तरह से मेल खाता है।

गौरैया की आबादी को संरक्षित करने में पक्षीघरों के महत्व को कम करके नहीं आंका जा सकता। तेजी से शहरीकरण और निवास स्थान के नुकसान ने इन प्यारे पक्षियों के लिए महत्वपूर्ण खतरे पैदा कर दिए हैं, जिससे उनकी संख्या में गिरावट आई है। बर्डहाउस सुरक्षित घोंसले के स्थान प्रदान करके जीवन रेखा प्रदान करते हैं, खासकर शहरी क्षेत्रों में जहां प्राकृतिक आवास दुर्लभ हैं।

दिल्ली एनसीआर, अपने हलचल भरे शहरी परिदृश्य के साथ, इस बात का एक मार्मिक उदाहरण है कि 'मेराघोसला.कॉम' जैसी पहल की सबसे अधिक आवश्यकता क्यों है। दिल्ली और बिहार के राज्य पक्षी के रूप में, गौरैया सांस्कृतिक और पारिस्थितिक महत्व रखती है। फिर भी, हाल के वर्षों में उनकी उपस्थिति कम हो गई है, जो संरक्षण प्रयासों की तात्कालिकता को रेखांकित करती है।

इंडियन ग्रीन बडी अभियान के माध्यम से, कुहू और उसके उत्साही ग्रीन दोस्त जागरूकता फैला रहे हैं और पर्यावरण शिक्षा को बढ़ावा दे रहे हैं। स्कूलों, समुदायों और व्यवसायों के साथ जुड़कर, उनका उद्देश्य प्रकृति के प्रति जिम्मेदारी की भावना पैदा करना और हरित भविष्य के लिए सामूहिक कार्रवाई को प्रेरित करना है।

जैसे-जैसे अभियान गति पकड़ता है, यह जमीनी स्तर की सक्रियता की शक्ति और उम्र की परवाह किए बिना व्यक्तियों के पर्यावरण संरक्षण पर पड़ने वाले प्रभाव के प्रमाण के रूप में कार्य करता है। मेराघोसला.कॉम (www.meraghosla.com) समुदाय, सहयोग और करुणा की भावना का प्रतीक है, यह दर्शाता है कि हर प्रयास, चाहे कितना भी छोटा क्यों न हो, मानव और वन्यजीवन दोनों के लिए समान रूप से एक उज्जवल कल में योगदान देता है।

Contact at indiangreenbuddy@gmail.c

दिल्ली के पूर्व मंत्री राजकुमार आनंद के पटेल नगर आवास के बाहर आप कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन

परिवहन विशेष न्यूज

दिल्ली मंत्रिमंडल और पार्टी से इस्तीफा देने के बाद कुछ लोगों ने शुक्रवार को राज कुमार आनंद के पटेल नगर आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। आप ने कहा है कि प्रदर्शन में आप कार्यकर्ता नहीं थे प्रदर्शन आम जनता ने किया है। उधर दिल्ली सरकार में निवर्तमान मंत्री राज कुमार आनंद ने कहा है कि प्रदर्शन आम आदमी पार्टी ने किया है।

नई दिल्ली। दिल्ली मंत्रिमंडल और पार्टी से इस्तीफा देने के बाद कुछ लोगों ने शुक्रवार को राज कुमार आनंद के पटेल नगर आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। आप ने कहा है कि प्रदर्शन में आप कार्यकर्ता नहीं थे, प्रदर्शन आम जनता ने किया है।

उधर दिल्ली सरकार में निवर्तमान मंत्री राज कुमार आनंद ने कहा है कि प्रदर्शन आम आदमी पार्टी ने किया है।मगर जनता समझ चुकी है अरविंद केजरीवाल और इनकी पार्टी शराब घोटाले में लिप्त है। इसलिए इनके पदाधिकारियों के अलावा जनता का कोई भी आदमी प्रदर्शन में नहीं आया।

कार्यकर्ताओं को भी पुलिस ने हिरासत में लिया

उधर प्रदर्शनकारियों ने कहा कि पिछले चार साल से आनंद आप के लिए काम कर रहे थे। उन्होंने उन लोगों से कई विकास परियोजनाओं का वादा किया था, जिन्होंने उन्हें वोट दिया था। उनके निर्वाचन क्षेत्र के लोग ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। इस दौरान कुछ कार्यकर्ताओं को भी पुलिस ने हिरासत में लिया।

वहीं एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि हमने कुछ आप कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया था, जिन्हें बात में छोड़ दिया गया।वे बिना किसी अनुमति के आनंद के घर के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे।

गिरफ्तारी के विरोध में आप का प्रदर्शन

पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए आम आदमी पार्टी ने बैनर लगाकर प्रदर्शन किया। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को आईटीओ फुटओवर ब्रिज और प्रगति मैदान फुटओवर ब्रिज पर हाथ में ''जेल का जवाब वोट से'' का बैनर लेकर शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन किया।

कार्यकर्ताओं ने कहा कि मोदी सरकार का मकसद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जेल में बंद करके पार्टी को खत्म करना है। पार्टी ने कहा कि केजरीवाल का कसूर सिर्फ इतना है कि उन्होंने दिल्ली के गरीब लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए अच्छे काम किए।

कार्यकर्ताओं कहा कि अरविंद केजरीवाल की रिहाई तक आम आदमी पार्टी सड़क से लेकर न्यायालय तक की लड़ाई जारी रखेगी। आईटीओ पर ह्यूमन बैनर प्रोटेस्ट में दिल्ली आम आदमी पार्टी के ओबीसी विंग के अध्यक्ष रविंद्र बालियान भी मौजूद थे।

आप के पास सरकार में रहने का नैतिक बल नहीं', राजकुमार आनंद का केजरीवाल पर हमला

अरविंद केजरीवाल सरकार से इस्तीफा देने के बाद राजकुमार आनंद ने आप जमकर हमला बोला है। भ्रष्टाचार बड़े बड़े नेता करें और एक आम पार्टी कार्यकर्ता धूप वर्षा सर्दी और गर्मी की चिंता किए बगैर तख्ती हाथ में लेकर धरने-प्रदर्शन में भाग लेता रहे। इसके साथ ही आनंद ने कहा कि मैं नहीं समझता कि हमारे पास सरकार में रहने का कोई नैतिक बस रह गया है।

नई दिल्ली। वरिष्ठ आप नेता आतिशी, सौरभ भारद्वाज और संजय सिंह के दावों से अलग दिल्ली सरकार के निवर्तमान समाज कल्याण मंत्री राजकुमार आनंद ने अपने इस्तीफे में कई गंभीर आरोप लगाए हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नाम लिखे गए दो पेज के इस्तीफे में आनंद ने स्पष्ट शब्दों में लिखा है, हमारे दो मंत्री जेल में हैं, सीएम भी जेल में हैं।

AAP सरकार को बताया आरक्षण विरोध

हमारी सरकार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं। मैं नहीं समझता कि हमारे पास सरकार में रहने का कोई नैतिक बस रह गया है। उन्होंने आम आदमी पार्टी और आप सरकार को आरक्षण और बाबा साहेब के विचारों की विरोधी भी बताया है। उन्होंने इस्तीफे में लिखा है, आज मैं जो कुछ भी हूं, बाबा साहेब की वजह से ही हूं। अलीगढ़ के ताले की फैक्ट्री में बाल मजदूरी की, ट्यूशन पढ़ाकर शिक्षा ग्रहण की, व्यवसाय किया, सामाजिक कार्य किए, राजनीति में आया, विधायक और मंत्री बना।

राजकुमार आनंद ने आगे कहा कि राजनीति में आने का मेरा उद्देश्य धन कमाना या सत्ता पाना नहीं है। मैं यहां आया, ताकि बाबा साहेब के सूत्र-समाज को वापस लौटाएं- को सच्चे अर्थों में साकार कर सकूं, लेकिन आपकी (केजरीवाल) सच्चाई कुछ और ही है। आप बाबा साहेब के आदर्शों पर चलने का दावा तो करते हैं, प्रेस वार्ता भी उनकी तस्वीर के साथ करते हैं, जबकि सच्चाई इससे अलग है।

आनंद ने अपने इस्तीफे में सीधा आरोप लगाया है, दिल्ली सरकार ने विधानसभा और मंत्रालयों में बड़ी तादाद में फैलो की भर्ती की। इनका वेतन भी लाखों में था, लेकिन इन भर्तियों में आरक्षण लागू करने की जरूरत नहीं समझी गई। अनुसूचित जाति-जनजाति के कल्याण का जो पैसा आता है, आप सरकार उसे किसी और योजना में खर्च करने में हिचकती नहीं है।

पार्टी कार्यकर्ताओं की लाचारी पर व्यक्त किया दुख

उन्होंने आगे लिखा कि आप में अनुसूचित जाति व जनजाति के पार्षद, विधायक और मंत्री का कोई सम्मान नहीं है। इस वर्ग के एक भी नेता को राज्यसभा सदस्य नहीं बनाया गया है। किसी को भी किसी प्रदेश का प्रभारी नहीं बनाया गया है, कोई किसी मंडी का अध्यक्ष नहीं है तो दिल्ली सरकार के 28 कॉलेजों में से एक में भी इस वर्ग का चैयरमेन नहीं है।

राजकुमार आनंद ने पार्टी कार्यकर्ताओं की लाचारी पर भी दुख व्यक्त किया है। उन्होंने लिखा कि सबसे बड़ा छल दिल्ली की जनता और हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ ही हुआ है। भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए उन्होंने आप, को सत्ता में बैठाया, जबकि आज यही पार्टी भ्रष्टाचार में डूबी है। पार्टी कार्यकर्ता बसें भरने की मशीन रह गए हैं।

भ्रष्टाचार बड़े बड़े नेता करें और एक आम पार्टी कार्यकर्ता धूप, वर्षा, सर्दी और गर्मी की चिंता किए बगैर तख्ती हाथ में लेकर धरने-प्रदर्शन में भाग लेता रहे। यह ठीक नहीं है, इसीलिए मेरे लिए इस सरकार में काम करना असहज हो गया है। मैं "आप" सरकार और इसके भ्रष्टाचार में अपना नाम नहीं जोड़ना चाहता।

जल्द ही आम लोगों के लिए खुलेगा दिल्ली का हेरीटेज पार्क, जानिए कितनी होगी एंट्री फीस

परिवहन विशेष न्यूज

दिल्ली का हेरीटेज पार्क को जल्द ही नागरिकों के लिए खोल दिया जाएगा। निगम ने प्रवेश की दरों को तय कर दिया है। वेस्ट टू वंडर पार्क में जो शुल्क है वहीं शुल्क यहां लगेगा। तीन साल तक के बच्चे के लिए प्रवेश इसमें निशुल्क होगा जबकि तीन से 12 वर्ष के बच्चे के लिए 25 रुपये का शुल्क होगा जबकि...

नई दिल्ली। दिल्ली के चौथे वेस्ट टू आर्ट पार्क बने हेरीटेज पार्क को जल्द ही नागरिकों के लिए खोल दिया जाएगा। आचार संहिता लागू होने से पहले ही इसका उद्घाटन हो चुका है। चूंकि प्रवेश की दरें तय नहीं हुई थी तो अभी यह नागरिकों के लिए नहीं खुला था। निगम ने प्रवेश की दरों को तय कर दिया है। वेस्ट टू वंडर पार्क में जो शुल्क है, वहीं शुल्क यहां लगेगा।

एमसीडी के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि पार्क में प्रवेश की दरें तय हो गई हैं। तीन साल तक के बच्चे के लिए प्रवेश इसमें निःशुल्क होगा, जबकि तीन से 12 वर्ष के बच्चे के लिए 25 रुपये का शुल्क होगा। 12 से 65 वर्ष के आयु वर्ग के लिए 50 रुपये का शुल्क होगा। 65 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के प्रवेश निशुल्क है। सप्ताहांत में यह तय शुल्क के दाम दोगुने हो जाते हैं।

उल्लेखनीय है कि अजमल खां पार्क में वाटिका में हेरीटेज पार्क तैयार वेस्ट टू आर्ट थीम पर तैयार किया है। इस पार्क में यूनेस्कों की सूचि में शामिल भारत की ऐतिहासिक इमारतों और स्थलों की प्रतिकृतियों को कबाड़ से बनाया गया है। इसमें 200 टन के करीब पुराने लोहे की टीन, साइकिल, कारों के पूर्जों को शामिल किया गया है। साढ़े चार एकड़ भूमि में इस पार्क में कबाड़ से बनी ही प्रतिकृतियां लगाई गई हैं।

इसमें दिल्ली का लाल किला, अहमदाबाद का तीन दरवाजा, मध्य प्रदेश का विष्णु मंदिर, कर्नाटक का दुर्गा मंदिर, जयपुर का अमेर किला, पश्चिम बंगाल का शांति निकेतन, गुजरात का चंपनेर, आगरा का किला, बिहार का महाबोधी मंदिर समेत अन्य राज्यों के प्रमुख स्थानों की कबाड़ से बनी प्रतिकृतिया लगाई है। इसी प्रकार श्री डी व्हील भी लगाए गए हैं।

कोर्णाक चक्र, धर्म चक्र , हंपी चक्र, एनीसेंट व्हील चक्र है। कुल 20 कलाकृति हैं। इसमें पांच चक्र हैं। पार्क में 22 हजार से अधिक सजावटी पौधे भी लगाए गए हैं ताकि लोग इनसे आकर्षित हो सकें। साढ़े तीन करोड़ की लागत से यह पार्क तैयार हुआ है। सांसद मीनाक्षी लेखी ने इसके लिए अपने सांसद निधि से फंड उपलब्ध कराया था।

दिल्ली में 3 दिन बारिश, तेज हवाओं के साथ छाए रहेंगे बादल; आईएमडी ने जारी किया अलर्ट

तेज धूप और गर्मी के बाद अब दिल्ली वालों को राहत मिलने वाली है। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से अगले तीन दिन राजधानी में बादल तेज हवा और वर्षा का दौर बने रहने के आसार हैं। इसके चलते अधिकतम तापमान में छह डिग्री तक की गिरावट आ सकती है। रविवार को यह 33 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है।

नई दिल्ली। मौसमी उतार चढ़ाव के बीच अब शुक्रवार का दिन दिल्ली में इस साल का अब तक का सबसे गर्म दिन रहा। अधिकतम तापमान सामान्य से तीन डिग्री अधिक दर्ज किया गया। मौसम विभाग की मानें तो पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से अगले तीन दिन राजधानी में बादल, तेज हवा और वर्षा का दौर बने रहने के आसार हैं।

पीतमपुरा में रहा सबसे ज्यादा गर्म

दिनभर खिली रही तेज धूप के चलते शुक्रवार को अधिकतम तापमान 39.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इससे पहले बुधवार को 39.1 डिग्री रहा था। वहीं न्यूनतम तापमान सामान्य से एक डिग्री अधिक 21.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हवा में नमी का स्तर 72 से 26 प्रतिशत रहा। नजफगढ़ में अधिकतम तापमान सर्वाधिक 40.4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जबकि पीतमपुरा रात सबसे ज्यादा गर्म रहा। यहां का न्यूनतम तापमान 24.5 डिग्री सेल्सियस रहा।

मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि शनिवार की शाम से ही पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिल सकता है। इसके चलते अधिकतम तापमान में छह डिग्री तक की गिरावट आ सकती है। रविवार को यह 33 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। इस दौरान हवा की गति भी 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक की हो सकती है। शनिवार और रविवार के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया गया है।

लगातार तीसरे दिन खराब रही हवा

शुक्रवार को लगातार तीसरे दिन दिल्ली की हवा खराब श्रेणी में दर्ज की गई। दिल्ली के ज्यादातर इलाकों का एक्यूआइ 200 के ऊपर रहा। इसकी वजह धूल और धुएं के कणों में हुई बढ़ोतरी को माना जा रहा है।केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के मुताबिक शुक्रवार को दिल्ली का एक्यूआइ 231 रहा। इस स्तर की हवा को खराब श्रेणी में रखा जाता है। एक दिन पहले बृहस्पतिवार को यह 238 रहा था।

अरविंद केजरीवाल को जेल भेजने का जनता में जबरदस्त गुस्सा है। जनता जेल का जवाब दिल्ली और पंजाब में वोट से देगी

'सीएम केजरीवाल को जेल भेजना भाजपा को पड़ेगा मंहगा'

सुनीता केजरीवाल से मुलाकात के बाद पंजाब से राज्य सभा सांसदों का जवाब

परिवहन विशेष न्यूज

'आप' के राष्ट्रीय महासचिव संगठन डॉ. संदीप पाठक के साथ राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा विक्रम साहनी और अशोक मित्तल ने सुनीता केजरीवाल से उनके आवास पर मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि हम पार्टी के साथ पूरी निष्ठा और ईमानदारी से खड़े हैं। इस संकट की घड़ी में हम सभी एकजुट हैं। जनता जेल का जवाब दिल्ली और पंजाब में वोट से देगी।

नईदिल्ली। पंजाब से आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसदों ने गुरुवार देर शाम को सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल से मुलाकात की। उन्होंने सुनीता केजरीवाल से कहा कि हम पूरी मजबूती से अरविंद केजरीवाल के साथ खड़े हैं। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक एवं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को तथाकथित शराब मामले में जेल जाने के बाद पंजाब से 'आप' सांसदों की सुनीता केजरीवाल से यह पहली मुलाकात है।

'आप' के राष्ट्रीय महासचिव संगठन डॉ. संदीप पाठक के साथ राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा, विक्रम साहनी और अशोक मित्तल ने सुनीता केजरीवाल से उनके आवास पर मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि हम पार्टी के साथ पूरी निष्ठा और ईमानदारी से खड़े हैं। इस संकट की घड़ी में हम सभी एकजुट हैं। सांसदों ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को जेल भेजने का जनता में जबरदस्त गुस्सा है। जनता जेल का जवाब दिल्ली और पंजाब में वोट से देगी।

सांसदों ने तस्वीरें भी की शेयर

पंजाब से 'आप' राज्यसभा सभा सदस्य संजीव अरोड़ा ने सुनीता केजरीवाल से मुलाकात के दौरान ली गई तस्वीर को अपने आधिकारिक एक्स (ट्वीटर) हैंडल पर साझा भी किया। सुनीता केजरीवाल के साथ पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव संगठन एवं राज्यसभा सदस्य डॉ. संदीप पाठक, सांसद संजीव अरोड़ा, विक्रम साहनी और अशोक मित्तल भी मौजूद रहे।

केजरीवाल के साथ मजबूती से हैं खड़े

राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा ने कहा कि आज राज्यसभा सांसद संदीप पाठक, सांसद विक्रम साहनी, सांसद अशोक मित्तल की मौजूदगी में मुख्यमंत्री आवास पर अरविंद केजरीवाल की धर्मपत्नी सुनीता केजरीवाल से मुलाकात की। उनका साहस और दृढ़ता संघर्ष के प्रतीक के रूप में दमक रहा है। सभी सांसदों ने सुनीता केजरीवाल को कहा कि वह अरविंद केजरीवाल के साथ पूरी मजबूती से खड़े हैं। अरविंद केजरीवाल जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं। भाजपा को उन्हें जेल भेजना भारी पड़ेगा।

'कांग्रेस के लिए लाठी-डंडे खाए, जेल गया', पार्टी के इस पुराने नेता ने सोनिया-राहुल को चिट्ठी लिख टिकट की लगाई गुहार

दिल्ली कांग्रेस के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष और पूर्व विधायक जयकिशन ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी राहुल गांधी वरिष्ठ नेता प्रियंका वाड्रा और केसी वेणुगोपाल को पत्र लिखकर अपने स्वयं के नाम पर भी विचार करने की गुहार लगाई है। उन्होंने पत्र में लिखा कि किसी भी विरोधियों के बहकावे में न आएं और हमें उम्मीदवार घोषित करें।

नई दिल्ली। दिल्ली की अपने हिस्से की तीनों लोकसभा सीटों के लिए कांग्रेस जहां अभी तक माथापच्ची में लगी हुई है, वहीं प्रदेश कांग्रेस का एक खेमा संभावित उम्मीदवारों के नामों से सहमत नहीं है। इस खेमे का प्रयास अब भी इसमें बदलाव करवाने का है। इसी कड़ी में पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष और पूर्व विधायक जयकिशन ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी, वरिष्ठ नेता प्रियंका वाड्रा और केसी वेणुगोपाल को पत्र लिखकर अपने स्वयं के नाम पर भी विचार करने की गुहार लगाई है।

मेरी वफादारी से सभी परिचितः जयकिशन

जयकिशन ने पत्र में लिखा है कि उनके राजनीतिक जीवन, वफादारी और ईमानदारी के बारे में पार्टी में सभी अच्छे से परिचित हैं। पार्टी के लिए उन्होंने समय समय पर कई बार धरना, प्रदर्शन, लाठी-डंडे खाए, संघर्ष किया और जेल भी गए। उन्होंने दावा किया है कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों के लिए भी उनसे ज्यादा काम किसी ने नहीं किया।

विरोधियों के बहकावे में न आएं: जयकिशन

इस पत्र के माध्यम से उनका कहना है लोकसभा चुनाव नजदीक हैं तो उनके विरोधियों के बहकावे में नहीं आएं। उनका राजनीतिक कैरियर खत्म करने में पार्टी को फायदा नहीं होगा। उनका दावा है कि उनके साथ अनुसूचित जाति एवं जनजाति के बहुत लोग जुड़े हुए हैं, उनका अपमान नहीं करें। मेरी वफादारी पर भरोसा रखा जाए। साथ ही जय किशन ने पार्टी आलाकमान को चेताया भी है कि लोकसभा चुनाव में उनकी अनदेखी का नतीजा अच्छा नहीं होगा।

एटीएस एडवांटेज सोसायटी की 23वीं मंजिल से कूदकर 12वीं के छात्र ने दी जान, सुसाइड नोट में लिखी ये बातें

परिवहन विशेष न्यूज

गाजियाबाद में 12वीं के एक छात्र ने 23वीं मंजिल से कूदकर अपनी जान दे दी। घटना इंदिरापुरम कोतवाली क्षेत्र के अहिंसा खंड एक स्थित एटीएस एडवांटेज सोसायटी में घटी। छात्र को पास के निजी अस्पताल ले जाया गया जहां से डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। उसकी जेब से सुसाइड नोट मिला है। पुलिस आत्महत्या के कारण की जांच कर रही है।

गाजियाबाद। इंदिरापुरम कोतवाली क्षेत्र के अहिंसा खंड एक स्थित एटीएस एडवांटेज सोसायटी की 23वीं मंजिल से कूदकर 12वीं के छात्र ने गुरुवार रात को जान दे दी। छात्र को पास के निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां से डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। उसकी जेब से सुसाइड नोट मिला है। पुलिस आत्महत्या के कारण की जांच कर रही है।

पुलिस के मुताबिक, पीड़ित परिवार छात्र बृहस्पतिवार शाम को अपने दो दोस्तों के साथ एटीएस एडवांटेज सोसायटी के टावर नंबर 21 में रहने वाले दोस्त के पास आया था। यहां से सभी दोस्त घूमने के लिए सोसायटी के टावर नंबर 21 के 24 फ्लोर छत पर चले गए। यहां सभी दोस्त एक दूसरे के फोटो खींचने लग गए। तभी छात्र अपने अन्य दोस्तों को नीचे जाने की बात कहकर वहां से चला गया।

23वीं मंजिल से कूदा और चौथे फ्लोर पर गिरा

वह एक फ्लोर नीचे 23वीं मंजिल पर पहुंचा। वहां से नीचे कूद गया। चौथे फ्लोर पर शॉफ्ट पर आकर वह गिरा। गिरने की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। उसे पास के निजी अस्पताल लेकर पहुंचे। जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने स्वजन को मामले की सूचना दी। पुलिस ने फारेंसिक टीम को मौके पर बुलाया। टीम ने मौके से साक्ष्य एकत्र किए हैं।

24वीं मंजिल से कूदा तो मौत निश्चित

घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस अस्पताल पहुंची। जहां डॉक्टरों को मृतक छात्र की जेब से एक रजिस्टर के पेज पर लिखा नोट मिला है। जिसमें सबसे ऊपर सुसाइड लिखा है और नीचे अंग्रेजी में लिखा कि मेरे प्रिय अगर में 24वीं मंजिल से नीचे कूदता हूं तो मौत निश्चित है। यह नोट डाक्टरों ने पुलिस को सौंप दिया है। पुलिस ने छात्र के स्वजन से छात्र के हैंड राइट का मिलान करने के लिए कापी मांगी है।

खंगाले जा रही हैं सीसीटीवी, की जा रही पूछताछ

घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस उपायुक्त ट्रांस हिंडन निमिष पाटिल, सहायक पुलिस आयुक्त इंदिरापुरम स्वतंत्र कुमार सिंह, थाना प्रभारी निरीक्षक इंदिरापुरम पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे।टीम टावर में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है।23वीं मंजिल पर लगे कैमरे की फुटेज भी देख रही है। छात्र के साथ घूमने के लिए गए सभी दोस्तों से भी जानकारी कर रही है। घटना के बाद से स्वजन सदमे में हैं। पुलिस उनसे भी छात्र के बारे में अन्य जानकारी करेगी।

नमो भारत ट्रेन ने बनाया एक नया कीर्तिमान

गुरुवार को एक दिन में सर्वाधिक यात्रियों ने किया सफर

परिवहन विशेष न्यूज

नमो भारत ट्रेन ने गुरुवार को एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। दरअसल गुरुवार को पहली बार नमो भारत ट्रेन में एक दिन में 13500 यात्रियों ने सफर कर रिकार्ड बनाया है। अक्टूबर 2023 से अब तक एक दिन में नमो भारत ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों की यह संख्या सर्वाधिक है। 20 अक्टूबर 2023 को प्रधानमंत्री मोदी ने साहिबाबाद ट्रेन का परिचालन यात्रियों के लिए शुरू किया था।

गाजियाबाद। देश की पहली नमो भारत ट्रेन का परिचालन गाजियाबाद में यात्रियों के लिए साहिबाबाद से मोदीनगर तक हो रहा है। इस ट्रेन में यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। बृहस्पतिवार को पहली बार एक दिन में 13,500 यात्रियों ने सफर कर रिकार्ड बनाया है। बृहस्पतिवार को अक्टूबर 2023 से अब तक एक दिन में नमो भारत ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों की संख्या सर्वाधिक रही।

82 किलोमीटर लंबे दिल्ली-गाजियाबाद- मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर का निर्माण कार्य तीन चरणों में कार्य किया जा रहा है। पहले चरण में साहिबाबाद से दुहाई के बीच कार्य अक्टूबर माह में पूरा हो गया। 20 अक्टूबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने साहिबाबाद ट्रेन का परिचालन यात्रियों के लिए शुरू किया था। दूसरे चरण में दुहाई से मोदीनगर तक का कार्य भी पूरा हो गया है।

नमो भारत ट्रेन में यात्रियों की संख्या बढ़ रही

मार्च 2024 से साहिबाबाद से मोदीनगर तक यात्रियों के लिए ट्रेन का परिचालन किया जा रहा है। पहले चरण की शुरुआत के बाद रोजाना तीन हजार और दूसरे चरण का कार्य पूरा होने के बाद रोजाना 10 हजार यात्रियों के सफर का अनुमान था। कम समय में अधिक दूरी की यात्रा पूरी करने वाली नमो भारत ट्रेन में आरामदायक सफर होने के कारण यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। एनसीआरटीसी के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पुनीत वत्स ने बताया कि बृहस्पतिवार को 13,500 यात्रियों ने साहिबाबाद से मोदीनगर के बीच आवागमन किया है, जो अब तक एक दिन में नमो भारत ट्रेन में सफर करने वालों की सबसे अधिक संख्या रही है।

रोजाना 8 नमो भारत ट्रेन का परिचालन

उन्होंने बताया कि साहिबाबाद से मोदीनगर के बीच 34 किमी. लंबे रूट पर यात्रियों के लिए रोजाना आठ नमो भारत ट्रेन का परिचालन किया जा रहा है। जून 2025 तक दिल्ली से मेरठ तक यात्रियों के लिए नमो भारत ट्रेन का परिचालन शुरू कर दिया जाएगा।

दिल्ली से गाजियाबाद जा रहा था कारोबारी, हिंडन एयरफोर्स के पास रोके गए; तलाशी में मिले इतने रुपये पुलिस भी हैरान

पुलिस के मुताबिक दिल्ली नजफगढ़ गुप्ता मार्केट के मोबाइल कारोबारी परवीन कुमार अपनी टाटा पंच कार में चालक विनोद के साथ गाजियाबाद जा रहे थे। रास्ते में हिंडन एयरफोर्स के पास पुलिस ने चेकिंग के दौरान उनकी कार रोक ली। कार की तलाशी ली गई तो कार से 22 लाख रुपये मिले। पुलिसकर्मियों ने आलाधिकारियों को मामले की जानकारी दी।

साहिबाबाद। कोतवाली क्षेत्र की हिंडन एयरफोर्स पुलिस चौकी के सामने चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक कार से 22 लाख रुपये मिले हैं। कारोबारी रुपये का हिसाब नहीं दे सका। पुलिस ने रुपया जब्त कर लिया है।

पुलिस के मुताबिक, दिल्ली नजफगढ़, गुप्ता मार्केट के मोबाइल कारोबारी परवीन कुमार अपनी टाटा पंच कार में चालक विनोद के साथ गाजियाबाद जा रहे थे।

पुलिस ने रोकी कार और फिर...

रास्ते में हिंडन एयरफोर्स के पास पुलिस ने चेकिंग के दौरान उनकी कार रोक ली। कार की तलाशी ली गई तो कार से 22 लाख रुपये मिले।

पुलिसकर्मियों ने आलाधिकारियों को मामले की जानकारी दी। सहायक पुलिस आयुक्त साहिबाबाद रजनीश कुमार उपाध्याय ने बताया कि रुपये के बारे में कारोबारी से जानकारी की गई। वह हिसाब नहीं दे सके। गाजियाबाद कहां जा रहे थे, इसके बारे में भी नहीं बताया। रुपया जब्त कर लिया है।

कान में ईयरबड लगाकर रेलवे ट्रैक पार कर रहा था शख्स, ट्रेन की चपेट में आकर मौत

परिवहन विशेष न्यूज

गाजियाबाद में कान में ईयरबड लगाकर रेलवे ट्रैक से गुजरना एक शख्स को भारी पड़ गया। ईयरबड पहनने की वजह से शख्स को ट्रेन की आवाज सुनाई नहीं दी और वह उसकी चपेट में आ गया। हादसा मोदीनगर में अंबर सिनेमा के सामने रेलवे ट्रैक पर बृहस्पतिवार शाम हुआ। युवक पार्क में दौड़ के लिए जा रहा था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव पोस्टमार्टम को भेजा।

गाजियाबाद। कान में ईयरबड लगाकर रेलवे ट्रैक से गुजर रहे युवक की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। हादसा मोदीनगर में अंबर सिनेमा के सामने रेलवे ट्रैक पर बृहस्पतिवार शाम हुआ। युवक पार्क में दौड़ के लिए जा रहा था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव पोस्टमार्टम को भेजा। युवक के मौत की सूचना के बाद से ही परिवार में कोहराम मचा है। स्वजन का रो रोकर बुरा हाल है।

कोतवाली क्षेत्र के मोहन पार्क कॉलोनी के राजीव राठी व्यवसायी हैं। घर में पत्नी व बेटे निखिल उर्फ चीकू (21) के साथ रहते हैं। निखिल एकलौता बेटा था। वह सेना भर्ती की तैयारी के लिए रोजाना शाम के समय हापुड़ रोड स्थित गांधी मैदान में दौड़ लगाने जाता था। बृहस्पतिवार शाम को भी गांधी मैदान में ही जा रहा था। अंबर के सामने रास्ते से रेलवे ट्रैक पर पहुंचा और गांधी मैदान की तरफ चलने लगा।

मेरठ की तरफ से आ रही ट्रेन

कान में ईयरबड लगा रखे थे। इसी बीच मेरठ की तरफ से ट्रेन आ रही थी। कान में ईयरबड के चलते उन्होंने ट्रेन के हार्न की आवाज नहीं सुनी और ट्रेन की चपेट में आ गए। मौके पर मौत हो गई। आसपास से गुजर रहे लोगों ने हादसे की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंचीं पुलिस ने शव की शिनाख्त कर स्वजन को सूचना दी। कुछ ही देर में माता-पिता मौके पर पहुंचे। बेटे के शव को देख दोनों फूट-फूटकर रोने लगे।

आसपास के लोगों ने उनका ढांढस बांधा। एसीपी मोदीनगर ज्ञान प्रकाश राय ने बताया कि प्राथमिक जांच में कान में ईयरबड के चलते हादसे की बात सामने आ रही है। शव पोस्टमार्टम को भेजकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।

दिल्ली से गाजियाबाद जा रहा था कारोबारी, हिंडन एयरफोर्स के पास रोके गए; तलाशी में मिले इतने रुपये पुलिस भी हैरान

पुलिस के मुताबिक दिल्ली नजफगढ़ गुप्ता मार्केट के मोबाइल कारोबारी परवीन कुमार अपनी टाटा पंच कार में चालक विनोद के साथ गाजियाबाद जा रहे थे। रास्ते में हिंडन एयरफोर्स के पास पुलिस ने चेकिंग के दौरान उनकी कार रोक ली। कार की तलाशी ली गई तो कार से 22 लाख रुपये मिले। पुलिसकर्मियों ने आलाधिकारियों को मामले की जानकारी दी।

साहिबाबाद। कोतवाली क्षेत्र की हिंडन एयरफोर्स पुलिस चौकी के सामने चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक कार से 22 लाख रुपये मिले हैं। कारोबारी रुपये का हिसाब नहीं दे सका। पुलिस ने रुपया जब्त कर लिया है।

पुलिस के मुताबिक, दिल्ली नजफगढ़, गुप्ता मार्केट के मोबाइल कारोबारी परवीन कुमार अपनी टाटा पंच कार में चालक विनोद के साथ गाजियाबाद जा रहे थे।

पुलिस ने रोकी कार और फिर...

रास्ते में हिंडन एयरफोर्स के पास पुलिस ने चेकिंग के दौरान उनकी कार रोक ली। कार की तलाशी ली गई तो कार से 22 लाख रुपये मिले।

पुलिसकर्मियों ने आलाधिकारियों को मामले की जानकारी दी। सहायक पुलिस आयुक्त साहिबाबाद रजनीश कुमार उपाध्याय ने बताया कि रुपये के बारे में कारोबारी से जानकारी की गई। वह हिसाब नहीं दे सके। गाजियाबाद कहां जा रहे थे, इसके बारे में भी नहीं बताया। रुपया जब्त कर लिया है।

क्या गाजियाबाद के 'भगवा' किले पर फहराएगा 'तिरंगा' ?

गाजियाबाद लोकसभा सीट की मुख्य चुनावी लड़ाई एनडीए समर्थित भाजपा प्रत्याशी अतुल गर्ग और इंडिया गठबंधन की कांग्रेस-सपा-आप प्रत्याशी डॉली शर्मा के बीच होगी। हालांकि दलित और क्षत्रिय वोटों के सहारे बसपा प्रत्याशी नंद किशोर पुंडीर इस लड़ाई को त्रिकोणात्मक बनाने में सफल हो जाएंगे।

Powered By

कमलेश पांडे

देश की राजधानी नई दिल्ली से सटी औद्योगिक नगरी गाजियाबाद में लोकसभा चुनाव धीरे-धीरे जोर पकड़ रहा है। आम चुनाव 2024 के तहत यहां दूसरे चरण में 26 अप्रैल को मतदान होगा, इसलिए पक्ष-विपक्ष के बीच राजनीतिक तपिश बढ़ती जा रही है। यहां की मुख्य चुनावी लड़ाई एनडीए समर्थित भाजपा प्रत्याशी अतुल गर्ग और इंडिया गठबंधन की कांग्रेस-सपा-आप प्रत्याशी डॉली शर्मा के बीच होगी। हालांकि दलित और क्षत्रिय वोटों के सहारे बसपा प्रत्याशी नंद किशोर पुंडीर इस लड़ाई को त्रिकोणात्मक बनाने में सफल हो जाएंगे। यदि ऐसा हुआ तो सियासी ऊंट किस करवट बैठेगा, कुछ कहा नहीं जा सकता।

अब आइए बात करते हैं उन पहलुओं पर जो इस चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं:-

पहला फैक्टर है- शहरी बनाम ग्रामीण। आमतौर गाजियाबाद महानगर के शहरी इलाकों में जहां भाजपा की पैठ मजबूत है, वहीं ग्रामीण इलाकों में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की पकड़ मजबूत है। वर्तमान में सपा कांग्रेस की सहयोगी पार्टी है। जबकि बसपा की पैठ शहरी/ग्रामीण दोनों इलाकों के जातिविशेष में है। बता दें कि गाजियाबाद की 70 प्रतिशत आबादी शहरों में और 30 प्रतिशत आबादी गांवों में निवास करती है। इस मामले में कांग्रेस पर भाजपा भारी पड़ सकती है।

दूसरा फैक्टर है- जातीय समीकरण। जो किसी एक प्रत्याशी के पक्ष में विरले ही जाता है। एक आंकड़े के मुताबिक, कुल 29 लाख 38 हजार 845 मतदाताओं वाली इस सीट पर सर्वाधिक 18 प्रतिशत ब्राह्मण, 15 प्रतिशत मुस्लिम, 14 प्रतिशत ठाकुर, 12 प्रतिशत गुर्जर, 10 प्रतिशत वैश्य, 16 प्रतिशत

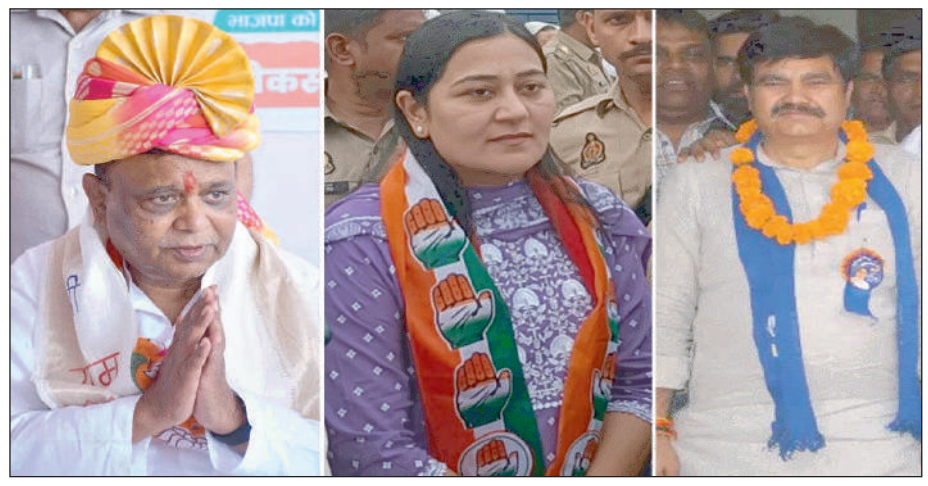

वंचित और 15 प्रतिशत अन्य मतदाता हैं। चूंकि भाजपा ने वैश्य, कांग्रेस ने ब्राह्मण और बसपा ने क्षत्रिय प्रत्याशी उतारे हैं। ये तीनों जाति भाजपा की हार्ड कोर समर्थक मानी जाती है।

शायद इसलिए भी कांग्रेस और बसपा ने उसी में सेंध लगाने की पहल की है। हालांकि, जातीय समीकरण भी अभी भाजपा के पक्ष में है क्योंकि उसने दलित, पिछड़े व पसमांदा मुसलमानों को जोड़ने की पहल शिद्दत पूर्वक की है, जबकि कांग्रेस इसे तोड़ने के लिए तरह-तरह के प्रयोग/उपाय कर रही है। लिहाजा, यहां भी भाजपा का पलड़ा कांग्रेस पर भारी है।

राजनीतिक विश्लेषकों की राय है कि पिछले 2 लोकसभा चुनावों से काँग्रेस के वोट बैंक में भाजपा सेंध लगा चुकी है, जिसे वापस पाना अब भी कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है। क्योंकि गरीबी हटाओ के नारे पर हिंदुत्व भारी पड़ चुका है। क्षद्म धर्मनिरपेक्षता पर राष्ट्रवाद हावी होकर बोल रहा है। वहीं, जातिविशेष पर बसपा की पकड़ से भी इंकार नहीं किया जा सकता है। इसलिए मौजूदा चुनावी लड़ाई दिलचस्प मोड़ लेती जा रही है।

तीसरा फैक्टर है- सांप्रदायिक गोलबंदी। यह बात साफ है कि भाजपा को हिंदुओं के वोट थोक भाव में मिलते हैं, जबकि अल्पसंख्यक समाज का वोट रणनीतिक रूप से थोड़ा-बहुत। वहीं, कांग्रेस व उसके समाजवादी समर्थकों को अल्पसंख्यक समाज का वोट थोक भाव में मिलता है, जबकि बहुसंख्यक हिंदुओं के वोट जातीय आधार पर रणनीतिक रूप से थोड़ा बहुत। आंकड़े गवाह हैं कि जहां भी सांप्रदायिक गोलबंदी होती है, वहां भाजपा को ज्यादा, कांग्रेस को कम फायदा मिलता है। वहीं, अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में यह स्थिति उलट जाती है।

चौथा फैक्टर है- सरकारी कामकाज और विभिन्न मुद्दे। इस चुनाव में भाजपा प्रत्याशी अतुल गर्ग जहां मोदी सरकार और योगी सरकार की उपलब्धियां गिना रहे हैं। अपने शहर विधायक होने और उत्तरप्रदेश में राज्यमंत्री के रूप में सेवा देने के बारे में भी बता रहे हैं। साथ ही राष्ट्रीय मुद्दों की भी बात कर रहे हैं। वहीं, कांग्रेस प्रत्याशी डॉली शर्मा कोरोना काल में अतुल गर्ग के यूपी के स्वास्थ्य राज्यमंत्री रहते हुए भी उनके द्वारा बरती गई लापरवाही पर लगातार उन्हें घेर रही हैं।

इसके अलावा, भाजपा द्वारा केंद्रीय मंत्री जनरल वी के सिंह का टिकट काटने पर भी उनकी पार्टी को आड़े हाथों ले रही हैं। यही नहीं, स्थानीय मुद्दों पर भी उन्हें लगातार घेर रही हैं। उनका आरोप है कि विगत 15 सालों से भाजपा के सांसद हैं, लेकिन मलिन बस्तियों तक विकास की किरण नहीं पहुंची है। गांवों में भी विकास नदारत है। इसलिए उन्होंने दो टूक कहा है कि गाजियाबाद का चुनाव वो स्थानीय मुद्दों पर भी लड़ेंगी। क्योंकि शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रदूषण, स्वच्छता, सुरक्षा, मेट्रो पहुंच आदि को वह सबके अनुकूल करने का इरादा रखती हैं। महंगाई व बेरोजगारी दूर करने का जज्बा रखती हैं। यहां पर कांग्रेस का पलड़ा कैंडिडेट के तेवर की वजह से भारी है और यही तेवर उनकी असली सियासी पूंजी है।

पांचवां फैक्टर है- संगठन और उसके दांवपेंच। इस मामले में भाजपा का कोई मुकाबला नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके ऊपर आरएसएस का परोक्ष हाथ हमेशा से ही रहता आया है। कांग्रेस भी अपने सेवा दल के सहारे देश पर लंबे समय तक राज कर चुकी है, जो अब कमजोर हो चुकी है। वहीं, नई आर्थिक नीतियों के दुष्परिणाम स्वरूप समाज में ऐसी प्रतिस्पर्धा बढ़ी कि सेवा भाव अब लगभग गायब होते जा रहा है और श्रम मूल्य सामाजिक जीवन में प्रभावशाली स्थान लेता जा रहा है।

वहीं, कांग्रेस की सहयोगी पार्टी सपा और आप के कैडर तो हैं, लेकिन ये भाजपा की रणनीति का मुकाबला कितने कारगर ढंग से कर पाते हैं, सबकुछ इस बात पर ही निर्भर करेगा। हालांकि पारस्परिक समन्वय बिठाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। वहीं, बसपा के पास लगभग 20 प्रतिशत कैडर वोट है, जिसके सहारे भारतीय राजनीति में उसकी पूछ निरंतर बनी हुई है। जबकि गत 12 वर्षों से वह यूपी की सत्ता से बाहर है।

ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या मीडिया और सोशल मीडिया में अक्सर छाई रहने वाली कांग्रेस प्रत्याशी क्या भगवा किले पर कांग्रेसी तिरंगा फहरा पाएंगी? क्या लुंज-पुंज कांग्रेस संगठन के सहारे वह अपने गठबंधन सहयोगियों को साधकर अपना लक्ष्य पूरा कर पाएंगी? क्या अपनी आक्रामक सियासी शैली से वह शांतिप्रिय व सुशिक्षित शहरी मतदाताओं को लुभा पाएंगी? क्या सियासी रूप से अनुभवहीन लोगों की फौज का नेतृत्व करते हुए वह गाजियाबाद के मैदान को फतह कर पाएंगी? सधा हुआ जवाब तो यही मिल रहा है कि आज की तिथि में दिल्ली उनके लिए बहुत दूर तो नहीं, बल्कि सन्निकट भी नहीं है। आने वाले दिनों में उन्हें कई सियासी पापड़ भी बेलने पड़ेंगे, लेकिन सवाल फिर वही कि क्या वह ऐसा कर पाएंगी? यदि नहीं तो अतुल का अतुलित सियासी बल उन्हें इस बार भी मात दे सकता है!

वरिष्ठ पत्रकार व राजनीतिक विश्लेषक

एमजी हेक्टर ब्लैक स्ट्रॉम वर्सेज सफारी डार्क एडिशन

जानें कौन सी एसयूवी को खरीदने में होगी समझदारी

ब्रिटिश वाहन निर्माता MG Motors की ओर से हाल में ही Hector SUV का Black Storm Edition भारतीय बाजार में लॉन्च किया गया है। वहीं इस सेगमेंट में Tata की ओर से Safari का Dark Edition भी बिक्री के लिए उपलब्ध करवाया जाता है। इन दोनों में से किस एसयूवी के डार्क एडिशन को खरीदना फायदेमंद होगा। आइए जानते हैं।

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। एमजी हेक्टर ब्लैक स्ट्रॉम एडिशन को हाल में ही भारतीय बाजार में लॉन्च किया गया है। लेकिन इस सेगमेंट में बाजार में Tata Motors की ओर से भी Safari का Dark Edition ऑफर किया जाता है। हम इस खबर में आपको बता रहे हैं कि इन दोनों में से किस एसयूवी के Dark Edition को खरीदने में फायदा मिल सकता है।

एमजी मोटर्स की ओर से मिड साइज एसयूवी के तौर पर ऑफर की जाने वाली Hector का Blackstorm Edition लॉन्च कर दिया गया है। कंपनी ने Gloster और Astor की तरह ही Hector के Blackstorm edition को भी ब्लैक और रेड कलर के साथ ऑफर किया है। इसके साथ इसमें गन मेटल एसेंट का भी उपयोग किया गया है। एमजी Hector BlackStorm Edition में डार्क क्रोम के साथ डायमंड मैश फ्रंट ग्रिल, स्किड प्लेट पर डार्क क्रोम इंसर्ट, टेलगेट गार्निश पर डार्क क्रोम, बॉडी साइड क्लैडिंग पर भी डार्क क्रोम फिनिश का उपयोग किया गया है। जिससे यह एसयूवी पावर और लग्जरी को पसंद करने वालों के लिए बेहतरीन विकल्प बन जाती है।

टाटा सफारी डार्क एडिशन

टाटा की ओर से सफारी के डार्क एडिशन को भी बाजार में ऑफर किया जाता है। इसमें हेक्टर की तरह ब्लैक के साथ किसी अन्य रंग का उपयोग नहीं किया जाता है। यह सिर्फ काले रंग में भी आती है। कंपनी की ओर से इस एसयूवी में Oberon Black रंग का उपयोग एक्सटीरियर में किया जाता है। इसके अलावा इस एडिशन में डार्क की बैजिंग को भी दिया जाता है।

कैसे हैं फीचर्स

एमजी ने इस एसयूवी के स्पेशल एडिशन में एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैंप, फ्लोटिंग लाइट टर्न इंडीकेटर, एलईडी ब्लेड कनेक्टिड टेल लैंप, फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 17.78 सेमी की एलसीडी स्क्रीन, वायरलैस एपल कार प्ले, एंड्राइड ऑटो, वायरलैस फोन चार्जर, पुश बटन स्टॉर्ट/स्टॉप के साथ स्मार्ट की, डिजिटल ब्लूटूथ की, 14 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम, 18 इंच के व्हील्स के साथ रेड कैलिपर, ड्यूल पैनोरमिक सनरूफ, ऑल ब्लैक लेदर अपहोल्स्ट्री, लेदर रैप स्टेयरिंग व्हील के साथ 75 कनेक्टिड फीचर्स और 100 वॉयस कमांड जैसे कई फीचर्स को ऑफर किया जा रहा है।

Tata Safari Dark Edition में भी काफी बेहतरीन फीचर मिलते हैं। इसमें पैनोरमिक सनरूफ, ब्लैक इंटीरियर, ब्लू एंबिएंट लाइट, ADAS, 31.24 cm इंफोटेनमेंट सिस्टम, पावर्ड को ड्राइवर सीट, ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, वेंटिलेटेड सीट्स, मेमोरी फंक्शन सीट, एबीएस, ईबीडी जैसे कई फीचर्स मिलते हैं।

कितनी है कीमत

कंपनी की ओर से Hector के Blackstorm edition को पांच, छह और सात सीटों के साथ भी ऑफर किया जा रहा है। इसके Sharp Pro वेरिएंट की एक्स शोरूम कीमत 21.25 लाख रुपये से शुरू हो जाती है। जबकि इस एडिशन के टॉप वेरिएंट को 22.76 लाख रुपये की एक्स शोरूम कीमत पर खरीदा जा सकता है।

टाटा सफारी के डार्क एडिशन की एक्स शोरूम कीमत 20.69 लाख रुपये से शुरू हो जाती है।

नए नाम से भारत आ सकती है फोर्ड एन्डेवर, जानें क्या होंगी खूबियां...

अमेरिकी कार निर्माता Ford एक बार फिर से भारतीय बाजार में वापसी की तैयारी कर रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी की ओर से अपनी फुल साइज एसयूवी Endeavor को जल्द ही भारत में पेश किया जा सकता है। कंपनी की ओर से इस SUV को किस नाम और खूबियों के साथ लाया जा सकता है। आइए जानते हैं।

नई दिल्ली। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक Ford एक बार फिर भारतीय बाजार में वापस आ सकती है। जानकारी के मुताबिक कंपनी फुल साइज एसयूवी के साथ भारतीय बाजार में वापसी करने की तैयारी कर रही है। इस एसयूवी में कंपनी किस तरह के फीचर्स को दे सकती है और इसे किस नाम से लाया जा सकता है। हम इसकी जानकारी आपको इस खबर में दे रहे हैं।

भारत आएगी Ford Endeavor

रिपोर्ट्स के मुताबिक फोर्ड की ओर से जल्द ही भारत में अपनी नई एसयूवी को पेश किया जा सकता है। कंपनी की ओर से जिस गाड़ी से भारत में वापसी की जा सकती है वह एसयूवी सेगमेंट की गाड़ी होगी। जानकारी के मुताबिक कंपनी अपनी एंडेवर की नई जनरेशन को भारत में सबसे पहले पेश करेगी। इसके बाद अन्य कारों को भी भारत लाया जा सकता है।

किस नाम से आएगी Ford Endeavor

रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी अपनी फुल साइज एसयूवी एंडेवर को एवरेस्ट नाम से भारत में ला सकती है। फिलहाल इसी नाम से इस एसयूवी को ऑस्ट्रेलिया और थाईलैंड जैसे कई देशों में ऑफर किया जाता है। ऐसे में कंपनी एंडेवर की जगह Everest के नाम से ही इसे भारत में भी पेश कर सकती है। इससे पहले कंपनी भारत में Endeavor नाम का उपयोग इसलिए करती थी क्योंकि तब Everest नाम को किसी और यूनिट के लिए ट्रेडमार्क किया गया था। लेकिन अब फोर्ड ने एवरेस्ट नाम के अधिकार हासिल कर लिए हैं।

कब तक आएगी भारत

अभी कंपनी की ओर से इस बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी है। लेकिन उम्मीद की जा रही है कि फोर्ड इस साल के आखिर तक भारतीय बाजार में अपनी नई एसयूवी को पेश कर सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी के साथ जुड़े एक सूत्र ने कहा है कि हम एवरेस्ट को अलग से नहीं बना सकते इसलिए इसे किसी और नाम की जगह एवरेस्ट नाम से ही लाया जा सकता है। कंपनी शुरू में इस एसयूवी को भारत में बनाने की जगह सीमित संख्या में बाहर से आयात कर सकती है।

क्या होंगी खूबियां

कंपनी की ओर से नई Endeavor को Everest नाम से लाने के साथ ही इसमें कई बेहतरीन खूबियों को भी दिया जाएगा। जानकारी के मुताबिक इसमें मेट्रिक्स हेडलाइट्स, एल शेप की रियर लाइट्स, 12 इंच टचस्क्रीन, पैनोरमिक सनरूफ, 12.4 इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ऑटो एसी, नौ एयरबैग, ADAS के अलावा भी कई बेहतरीन फीचर्स और सेफ्टी फीचर्स को ऑफर किया जाएगा।

1832 में हुई थी लॉन्च पहली इलेक्ट्रिक कार लेकिन सड़को पर नजर आने में लग गए 59 साल

दुनिया में इलेक्ट्रिक कारों का इतिहास कितना पुराना है? अगर ये सवाल आज किसी से पूछा जाए तो जवाब मिलेगा, करीब 10 या 15। अगर आप भी ऐसा सोच रहे हैं तो आप गलत सोच रहे हैं। आपको बता दें कि दुनिया में पहली इलेक्ट्रिक कार 1832 में स्कॉटलैंड में बनी थी और ठीक 59 साल बाद यानी 1891 में पहली इलेक्ट्रिक कार अमेरिका की सड़क पर दौड़ी थी। बेशक पहले के समय में इलेक्ट्रिक कारों में एसी, पावर स्टीयरिंग और आज के हाईटेक फीचर्स नहीं होते थे, लेकिन इन कारों ने भविष्य में इलेक्ट्रिक कारों की नींव जरूर रखी। ऐसे में 192 साल पुरानी इलेक्ट्रिक कार के इतिहास को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। दुनिया की पहली इलेक्ट्रिक कार 1832 में स्कॉटलैंड में रॉबर्ट एंडरसन नाम के एक मैकेनिक ने बनाई थी। एंडरसन ने सिंगल चार्ज बैटरी का उपयोग किया। इसके बाद दुनिया में ईवी बनाने की प्रक्रिया 1865 में फ्रांस में एसिड बैटरी का उपयोग करके बनाई गई दूसरी इलेक्ट्रिक कार, जिसके बाद 1891 में दुनिया की पहली आधिकारिक इलेक्ट्रिक कार अमेरिका की सड़कों पर देखी गई। 1960 के दशक में दुनिया में ईंधन की कमी हो गई थी, जिसके बाद कंपनियों ने ईवी पर ध्यान देना शुरू किया। 1975 में अमेरिकन मोटर कंपनी ने इलेक्ट्रिक डिलीवरी जीप पेश की। इसके बाद कई कंपनियों ने ईवी सेगमेंट में हाथ आजमाया। 2008 में टेस्ला ने रोडस्टर ईवी लॉन्च की, जिसने इलेक्ट्रिक कारों के बाजार को बदल दिया। भारत में पहली इलेक्ट्रिक कार साल 1993 में लॉन्च हुई थी। लव बर्ड दो सीटों वाली इलेक्ट्रिक कार थी, जिसकी सिंगल चार्जिंग पर रेंज 60 किलोमीटर थी। यह कार बाजार में टिक नहीं पाई और इसे कुछ ही समय में बंद करना पड़ा। आज के समय पूरी दुनिया में इलेक्ट्रिक कारों की मांग चरम पर है। टेस्ला अमेरिका और पूरी दुनिया में धूम मचा रही है। इसे टक्कर देने के लिए चीनी कंपनियों शाओमी और बीवाईडी ने कमर कस ली है। ऐसे में अब ये तीनों कंपनियां भारत को दुनिया के सबसे बड़े इलेक्ट्रिक कार बाजार के रूप में देख रही हैं। अगर दुनिया में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री की बात करें तो पिछले साल दुनिया भर में 14 करोड़ वाहन बेचे गए। जिसमें दोपहिया और चार पहिया इलेक्ट्रिक वाहन शामिल हैं। आने वाले दिनों में इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग तेजी से बढ़ने वाली है।

मर्सिडीज ने पिछले साल बेचीं 18 हजार से ज्यादा गाड़ियां, इस साल कर रही नौ कार एंड एसयूवी लाने की तैयारी

जर्मनी की लग्जरी कार निर्माता Mercedes Benz ने 2023-24 के वित्तीय वर्ष के दौरान भारत में बिक्री के मामले में पॉजिटिव ग्रोथ हासिल की है। इसके साथ ही कंपनी ने साल 2024 में आने वाली कई गाड़ियों की जानकारी भी दी है। कंपनी के लिए बीता वित्त वर्ष कैसा रहा और किन कारों को इस साल में पेश किया जा सकता है। आइए जानते हैं।

नई दिल्ली। जर्मनी की लग्जरी कार निर्माता Mercedes Benz के लिए बीता वित्त वर्ष काफी बेहतरीन रहा। कंपनी ने इस दौरान बड़ी संख्या में भारतीय बाजार में अपनी कारों की बिक्री की है। इसके साथ ही कंपनी ने इस साल पेश की जाने वाली कारों की भी जानकारी दी है। कंपनी ने बीते साल कितनी कारों की बिक्री की है और इस साल कितने नए मॉडल्स को भारतीय बाजार में ला सकती है। हम इसकी जानकारी आपको इस खबर में दे रहे हैं।

भारतीय बाजार में Mercedes Benz की मांग में बढ़ोतरी

कंपनी ने जानकारी दी है कि एसयूवी रेंज की मजबूत मांग के कारण 2023-24 में भारत में एक वित्तीय वर्ष में अपनी सबसे ज्यादा रिटेल सेल दर्ज की है। कंपनी ने पिछले वित्त वर्ष में 18,123 यूनिट्स की बिक्री की है, जबकि 2022-23 वित्त वर्ष में कंपनी ने 16,497 यूनिट्स की बिक्री की थी। 2022-23 के मुकाबले 2023-24 में यह आंकड़ा 10 प्रतिशत ज्यादा है। इस साल जनवरी से मार्च के बीच Mercedes Benz ने 5412 कारों की बिक्री की है, जो पिछले साल की पहली तिमाही की 4,697 इकाइयों से 15 प्रतिशत ज्यादा है।

कंपनी के अधिकारियों ने कही यह बात

मर्सिडीज बेंज इंडिया के एमडी और सीईओ संतोष अय्यर ने कहा, ₹हमने भारत में अब तक का सबसे अच्छा महीना, अब तक की सबसे ऊंची तिमाही और अब तक का सबसे अच्छा वित्तीय वर्ष हासिल किया है। यह विश्वास भारत में मर्सिडीज-बेंज के लिए बेजोड़ वांछनीयता को दर्शाता है, जिसके परिणामस्वरूप जबरदस्त ग्राहक प्रतिक्रिया मिली है।

इस साल आएंगे नौ मॉडल्स

लग्जरी कार निर्माता ने कहा कि वह इस साल देश में नौ नए मॉडल पेश करने की योजना बना रही है। जिसमें तीन नए बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन (BEV) शामिल हैं। कंपनी ने कहा कि वह इस कैलेंडर ईयर की दूसरी तिमाही में एएमजी एस 63 ई-परफॉर्मेंस सेडान और एएमजी सी 63 ई-परफॉर्मेंस के लॉन्च के साथ अपनी एएमजी परफॉर्मेंस रेंज को भी मजबूत करेगी।

कैसा है पोर्टफोलियो

मर्सिडीज बेंज की ओर से भारतीय बाजार में कई तरह की कारें और एसयूवी ऑफर की जाती हैं। कंपनी की ओर से एसयूवी सेगमेंट में GLA, GLC, GLE, GLS and G-Class को ऑफर किया जाता है। इसके साथ ही A-Class, C-Class, LWB E-Class, S-Class और LWB E-Class को सेडान के तौर पर बिक्री के लिए उपलब्ध करवाया जाता है। एसयूवी सेगमेंट के वाहनों पर कंपनी के मुताबिक दो महीने से लेकर एक साल तक का वेटिंग पीरियड चल रहा है।

टेस्ला इंडिया प्लान : तो ये है टेस्ला का भारत को लेकर प्लान! इसी महीने ख़ुद एलन मस्क कर सकते हैं खुलासा

पारिवहन विशेष न्यूज

अमेरिकी इलेक्ट्रिक कार निर्माता Tesla के प्रमुख Elon Musk इस महीने भारत दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरान उनकी मुलाकात PM Modi से होगी। जानकारी के मुताबिक इस मुलाकात के बाद Tesla का भारत को लेकर प्लान भी सार्वजनिक किया जा सकता है। टेस्ला के भारत आने को लेकर और क्या जानकारी इस दौरे के बाद मिल सकती है। आइए जानते हैं।

नई दिल्ली। टेस्ला के प्रमुख Elon Musk इस महीने भारत के दौरे पर आ रहे हैं। इसकी जानकारी उन्होंने खुद अपने सोशल मीडिया अकाउंट से की है। अपने दौरे पर वह कंपनी के भारत में आने को लेकर प्लान की जानकारी भी साझा कर सकते हैं। हम इस खबर में आपको बता रहे हैं कि मस्क की ओर से टेस्ला की भारत में एंट्री को लेकर और क्या जानकारी मिली है।

भारत आएंगे Tesla के Elon Musk

अपनी आगामी भारत यात्रा की पुष्टि करते हुए, Elon Musk ने बुधवार देर रात ट्वीट किया था कि वह प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए उत्सुक हैं। उन्होंने एक्स पर लिखा कि ₹भारत में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक की प्रतीक्षा कर रहा हूँ!

मस्क ने पहले कही थी यह बात

कुछ समय पहले एक एक्स स्पेस सत्र में, Elon Musk ने कहा था कि हर दूसरे देश की तरह भारत में भी Electric Cars होनी चाहिए और देश में Tesla इलेक्ट्रिक वाहन उपलब्ध कराना उनकी कंपनी के लिए एक स्वाभाविक प्रगति होगी।

हो सकती है अहम घोषणा

सूत्रों के मुताबिक, मस्क अपनी भारत यात्रा के दौरान देश में टेस्ला का पहला प्लांट स्थापित करने की बहुप्रतीक्षित घोषणा कर सकते हैं। रॉयटर्स के मुताबिक मस्क 22 अप्रैल को राष्ट्रीय राजधानी में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। भारत में टेस्ला के पहले प्रवेश की घोषणा करने के अलावा, मस्क से देश के लिए ऑटोमोबाइल प्रमुख की योजनाओं के विवरण का खुलासा करने की भी उम्मीद है। हालाँकि, मस्क की भारत यात्रा के अंतिम एजेंडे की पुष्टि होना अभी बाकी है।

भारत में हो रही थी खोज

पहले यह बताया गया था कि टेस्ला के अधिकारी एक विनिर्माण संयंत्र के लिए भारत में संभावित स्थलों की खोज कर रहे थे, जिसके लिए लगभग दो बिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश की आवश्यकता होने का अनुमान है। भारतीय बाजार में अपनी उपस्थिति बढ़ाने में टेस्ला की दिलचस्पी तेज हो गई है, कंपनी सक्रिय रूप से एक अत्याधुनिक विनिर्माण सुविधा स्थापित करने के लिए उपयुक्त स्थान की तलाश कर रही है।

सूत्रों के अनुसार, महाराष्ट्र और गुजरात की राज्य सरकारों ने इस उद्देश्य के लिए टेस्ला को आकर्षक भूमि की पेशकश की है, जो भारत के इलेक्ट्रिक मोबिलिटी परिदृश्य में महत्वपूर्ण प्रगति का संकेत है। जैसा कि पहले बताया गया था, शुरुआत में टेस्ला भारत में एंट्री-लेवल कारों का निर्माण करेगी, जिनकी कीमत लगभग 25 लाख रुपये होगी, जिसकी वार्षिक क्षमता 5 लाख यूनिट होगी।

क्या है नीति

नीति में न्यूनतम 4150 करोड़ रुपये (500 मिलियन अमेरिकी डॉलर) की निवेश सीमा मांगी गई है और निर्माताओं को घरेलू मूल्य संवर्धन (डीवीए) के महत्वपूर्ण स्तर हासिल करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है, सरकार का आदेश है कि विनिर्माण इकाई स्थापित करने के तीसरे वर्ष तक, कम से कम वाहनों को बनाने में इस्तेमाल होने वाले 25 फीसदी हिस्से घरेलू स्तर पर ही मिलने चाहिए। संचालन के पांचवें वर्ष तक यह स्थानीयकरण स्तर 50 प्रतिशत तक बढ़ने की उम्मीद है। नई ईवी नीति के तहत, 35,000 अमेरिकी डॉलर या उससे अधिक मूल्य के वाहनों के लिए, यदि निर्माता तीन साल के भीतर भारत में विनिर्माण सुविधाएं बनाता है, तो पांच साल के लिए 15 प्रतिशत सीमा शुल्क लगाया जाएगा। नीति के तहत आयात के लिए अनुमत ईवी की कुल संख्या किए गए निवेश के आधार पर सीमित होगी, या अधिकतम मूल्य 6484 करोड़ रुपये, जो भी कम हो। यदि निवेश 800 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक है, तो अधिकतम 40,000 ईवी का आयात किया जा सकता है, प्रति वर्ष 8,000 से अधिक नहीं। अप्रयुक्त आयात सीमा को आगे बढ़ाया जा सकता है।

पहले भी हुई थी मुलाकात

इससे पहले पिछले साल जून में, Elon Musk ने कहा था कि वह 2024 में भारत का दौरा करने की योजना बना रहे हैं, Musk ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि इलेक्ट्रिक कार निर्माता जल्द ही भारत में होगा और ₹जितनी जल्दी संभव हो सके₹ ऐसा करेंगे। उन्होंने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक के बाद न्यूयॉर्क में संवाददाताओं से कहा था, जो उस समय अमेरिका की चार दिवसीय राजकीय यात्रा पर थे। मस्क ने कहा था कि पीएम मोदी ने उन्हें भारत आने का न्योता दिया है। मस्क ने कहा था, ₹मैं पीएम मोदी को उनके समर्थन के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं और उम्मीद है कि हम भविष्य में कुछ घोषणा कर पाएंगे।₹ इसके बाद नवंबर 2023 में, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कैलिफोर्निया के फ्रेमोंट में टेस्ला की फैक्ट्री का दौरा किया था।

विपक्षी गठबंधन और कांग्रेस की प्रासंगिकता

कुलदीप चंद अग्निहोत्री

वायनाड ने सब गड़बड़ कर दिया। कम्युनिस्टों ने राहुल गांधी से पूछा कि आप तो पिछले दस साल से चिल्ला रहे हो कि आप की लड़ाई भाजपा वालों से है, लेकिन आप केरल में तो हमसे ही लड़ रहे हो। हम दिल्ली में आप के साथ एक मंच पर बैठ कर लम्बे-लम्बे भाषण देते हैं। मिल कर भाजपा के साथ लडने की हुंकार लगाते हैं, लेकिन उस सबके बावजूद आप केरल में हमसे ही लड़ रहे हैं'

भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए विपक्षी पार्टियों में जो सर्वाधिक व्याकुल प्राणी थे, उनमें से चार शिखर पर थे। नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, सोनिया गांधी और कम्युनिस्ट। प्रश्न पूछा जा सकता है कि मैंने अन्य दलों का नाम न लिख कर, उन दलों के प्रमुख व्यक्ति का नाम लिखा है, लेकिन कम्युनिस्टों के मामले में व्यक्ति का नाम न लिख कर केवल कम्युनिस्ट शब्द का प्रयोग क्यों किया है। उसका कारण है। हमारे भारत में कम्युनिस्ट सदा किसी शरीर की तलाश में रहते हैं। जब कम्युनिस्ट अपने शरीर में प्रकट होते हैं तो भारत के लोग उन्हें तुरंत पहचान लेते हैं और नकार देते हैं। इसलिए वे निरंतर किसी दूसरे शरीर, जिंदा या मुर्दा, की तलाश में रहते हैं और अपनी सुविधानुसार उसे पा भी लेते हैं। उनकी ऐसी पृष्ठभूमि में उनके किसी शीर्ष पुरुष का नाम पहचान पाना या तलाश करना बहुत मुश्किल है। उनके शीर्ष पुरुष आपस में इतने मिलेजुले हैं कि किसी को पहचान पाना ही मुश्किल है। इसलिए मैंने किसी व्यक्ति विशेष का नाम न लिख कर नंगा चिट्टा कम्युनिस्ट शब्द का प्रयोग ही किया है। अब आगे बढ़ा जाए। लेकिन हमारे आगे बढने से पहले ही नीतीश कुमार इंडी मोहल्ला छोड़ कर वापस अपने घर लौट गए हैं। ममता बनर्जी हैं अभी भी इंडी मोहल्ला में ही, लेकिन उस मोहल्ला के बाकी लोगों से उन्होंने बोलचाल बंद कर दी है।

उनकी पार्टी ने पश्चिम बंगाल की सभी सीटों पर अपने प्रत्याशी खड़े कर दिए हैं। लेकिन वैसे वे बराबर कह रही हैं कि वे इंडी के साथ मजबूती से खड़ी हैं और बंगाल को छोड़ कर बाकी सभी जगह उसका समर्थन कर रही हैं। लेकिन सोनिया गांधी इतना तो जानती हैं कि उनकी पार्टी को यदि ममता बनर्जी की जरूरत थी तो केवल बंगाल में थी। शेष भारत में, सोनिया गांधी तो क्या, ममता बनर्जी खुद भी जानती हैं कि उनकी हैसियत ही नहीं है। एक दूसरी पार्टी है जो इंडी गठबंधन में सर्वत्र विद्यमान है, लेकिन दिखाई नहीं देती। यह पार्टी अब भारत में 'अशरीरी' हो गई है। उसका नाम मुस्लिम लीग है। यह कांग्रेस के पैदा होने के कुछ साल बाद 1905 में पैदा हुई थी। कहा जाता है कि अंग्रेजों ने इस पार्टी को पैदा करने के लिए ही बंगाल का विभाजन किया था। मुस्लिम लीग को पैदा करने के बाद बंगाल विभाजन को भी खत्म कर दिया था। 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने अंग्रेजों से भारत के मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन मंडल की मांग की थी। बाद में संबंध बनते बिगड़ते गए, लेकिन कांग्रेस ने 1947 में अपनी कार्यसमिति की अंतिम बैठक में मुस्लिम लीग की भारत विभाजन की मांग का समर्थन करने के लिए 'भारत विभाजन' का प्रस्ताव पारित किया था। भारत विभाजन के बाद जब बचे-खुचे भारत में मुस्लिम लीग के लिए रहना मुश्किल हो गया, तो उसने अपनी शक्ल में प्लास्टिक सर्जरी करवा कर रूप बदल लिया था। उससे चेहरा तो बदल गया था, लेकिन भारत के लोग उनकी आवाज अच्छी तरह पहचानते ही हैं।

इसलिए वे बराबर चिल्ला रहे हैं। यह बदल रहे चेहरे से घूम रही वही मुस्लिम लीग है जिसने भारत का विभाजन करवाया था। लेकिन सोनिया जी का कहना है कि यह पुराने वाली मुस्लिम लीग नहीं है। यह नई ताजा मुस्लिम लीग है जिसका पुरानी मुस्लिम लीग से कोई ताल्लुक नहीं है। पता चला है कि कुछ पुराने कांग्रेसियों ने कान में बताया भी कि मैडम, आपको पुरानी वाली का पता नहीं है, क्योंकि आपकी पृष्ठभूमि इटली की है। यह मुस्लिम लीग शत प्रतिशत पुराने वाली मुस्लिम लीग ही है। लेकिन सोनिया गांधी नहीं मानी। वह उसी को सच मानती हैं जो राहुल-प्रियंका-राबर्ट वाड्रा बताते हैं। अब यह नई वाली मुस्लिम इंडी का हिस्सा है। उसका परिणाम भी सामने आने लगा है। सोनिया जी की पार्टी ने अपना जो चुनाव घोषणा पत्र जारी किया है, यदि उसको ध्यान से पढ़ा जाए, जिससे अंग्रेजी वाले 'टू रीड बिटवीन दी लाईन्ज' कहते हैं, तो वह काफी हद तक 1947 से पहले का मुस्लिम लीग के चुनाव घोषणा पत्र का नया संस्करण लग रहा है। अब तवलीन सिंह का कहना है कि आधा हिस्सा कम्युनिस्ट पार्टी का ही है। सोनिया गांधी जी की एक दूसरी समस्या भी है। वह मुस्लिम लीग का समर्थन तो लेना चाहती हैं, लेकिन यह नहीं चाहती कि लोग इसको जान लें। वैसे पूछा जा सकता है कि 'गुड़ तो खाएं, लेकिन गुलगुलों से परहेज' की इस नीति का कारण क्या है। जब अपने चुनाव घोषणा पत्र में मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र समेट लिया, अयोध्या में राम मंदिर में आने के निमंत्रण को सार्वजनिक रूप से ठुकरा दिया और मुस्लिम लीग को मंच पर भी बिठा लिया तो अब बचा क्या है? फिर यह हिचकिचाहट कैसी? यह संकट केरल के वायनाड में आया। राहुल गांधी अब उत्तर प्रदेश को छोड़ कर केरल चले गए हैं। केरल में भी मुस्लिम बहुल क्षेत्र वायनाड को उन्होंने अपने लिए चुना है। सारे देश में उन्हें लोकसभा में जाने के लिए अपनी पार्टी की विचारधारा और उसके अनुरूप मित्रों के कारण वायनाड ही सुरक्षित लगता है। यह पांच साल पहले ही स्पष्ट हो गया था जब राहुल गांधी को उत्तर प्रदेश की जनता ने अमेठी में ठुकरा दिया था और वायनाड ने उन्हें संकट के उस काल में सुरक्षा चक्र प्रदान किया था। तब बहुत से राजनीतिक विश्लेषक मानने लगे थे कि राहुल गांधी अब पांच साल मेहनत करके उत्तर प्रदेश के लोगों का विश्वास जीतेंगे।

लेकिन शायद सोनिया परिवार ने यह लंबा रास्ता अख्तियार करने की बजाय वायनाड का सुरक्षा चक्र लेना ही उचित समझा। लेकिन इस बार एक झंझट हो गया। राहुल गांधी दिल्ली से वायनाड तक की लंबी दूरी तय करके लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने वायनाड पहुंचे, तो स्वाभाविक ही मन में आया होगा कि शक्ति प्रदर्शन के लिए रोड शो भी कर लिया जाए। कांग्रेस पार्टी के झंडे बड़ी संख्या में तैयार कर लिए गए। स्वाभाविक है जो मुस्लिम लीग उनको सुरक्षा चक्र प्रदान करती है, उन्होंने शर्त लगा दी कि रोड शो में उनके झंडे भी बराबर लगेंगे। यह राहुल गांधी को स्वीकार नहीं था।

यदि रोड शो हुआ तो मुस्लिम लीग के झंडों के साथ ही। तब कांग्रेस ने इटली के मैकियावली को याद किया होगा। मध्य मार्ग। झंडा न कांग्रेस का लगेगा और न ही मुस्लिम लीग का। देश में शायद कांग्रेस का पहला रोड शो था जिसमें कांग्रेस के झंडों को ही मुस्लिम लीग को प्रसन्न करने के लिए, कांग्रेस के लिए ही हानिकारक मान लिया गया। लेकिन कांग्रेस की समस्याओं का हल केवल मुस्लिम लीग को प्रसन्न कर ही तो होने वाला नहीं लगता। मुस्लिम लीग खुश हुई, तो कम्युनिस्ट बोले। जैसा कि पहले ही मैंने लिखा है कम्युनिस्ट दो रूपों में हैं। पहला रूप वह जो कांग्रेस के शरीर के बीच ही घुस कर बैठा है। दूसरा रूप वह है जो शरीर से बाहर विद्यमान है। कई बार बाहर वाला शरीर प्रश्न करता है और अंदर वाला जवाब देता है। यह जवाब वही होता है जो बाहर वाले कम्युनिस्ट की हित साधना करता है। लेकिन वायनाड ने सब गड़बड़ कर दिया। कम्युनिस्टों ने राहुल गांधी से पूछा कि आप तो पिछले दस साल से चिल्ला रहे हो कि आप की लड़ाई भाजपा वालों से है, लेकिन आप केरल में तो हम से ही लड़ रहे हो। हम दिल्ली में आप के साथ एक मंच पर बैठ कर लम्बे लम्बे भाषण देते हैं। मिल कर भाजपा के साथ लडने की हुंकार लगाते हैं, लेकिन उस सबके बावजूद आप केरल में हमसे ही लड़ रहे हैं। सोनिया गांधी जी इसका क्या उत्तर दें? बहरहाल, कांग्रेस को पुनः अपना धरातल तलाशना चाहिए, अपनी उपयोगिता स्थापित करनी चाहिए। तभी उसका कल्याण होगा।

संपादक की कलम से

अब हेपेटाइटिस का संक्रमण

विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रपट में भारत में हेपेटाइटिस की चुनौतियों और खतरों का उल्लेख है। लिवर से जुड़ी यह बीमारी घातक भी साबित हो सकती है और बाद में कैंसर का रूप भी धारण कर सकती है। हेपेटाइटिस बी और सी को लेकर भारत में जागृति बहुत कम है, क्योंकि इनके लक्षण ही पेचीदा हैं। चूंकि यह भी वायरल संक्रमण की बीमारी है, लिहाजा डॉक्टर भी लक्षणों का अध्ययन करते समय गलत निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं। भारत में हेपेटाइटिस बी के करीब 3 करोड़ संक्रमित मरीज हैं, जबकि हेपेटाइटिस सी के 50 लाख से अधिक लोग बीमार हैं। लिवर की सूजन और संक्रमण के साथ इन बीमारियों का बोझ उठाने वाला भारत विश्व में ऐसा दूसरा देश है। वह दिन दूर नहीं, जब विश्व में सर्वाधिक हेपेटाइटिस संक्रमण भारत में होगा। भारत में ही 2022 में हेपेटाइटिस ने एक लाख से अधिक जिंदगियां छीन ली थीं। चिंताजनक पक्ष यह है कि बहुत कम संक्रमित लोगों के लक्षण स्पष्ट हो पाते हैं, लिहाजा वे निदान और इलाज के दायरे में नहीं आ पाते। हेपेटाइटिस सी के 30 फीसदी से कम मामलों की पहचान हो पाती है, लिहाजा लिवर का यह संक्रमण ज्यादा घातक, यहां तक कि जानलेवा, साबित हो सकता है। हेपेटाइटिस बी के आंकड़े मात्र 3 फीसदी ही बताए जाते हैं। नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम का लक्ष्य 2030 तक भारत को हेपेटाइटिस सी से मुक्त कराना है। हेपेटाइटिस बी से जुड़ी रुग्णता, मृत्यु-संख्या और मृत्यु-दर को भी 2030 तक ही काफी कम करना है। इसे लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन और भारत सरकार काफी आशान्वित हैं कि यदि 2024 और 2026 के बीच स्थितियों में सुधार लाया जाए, तो हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम पटरी पर लाया जा सकता है। नतीजतन लक्ष्य भी कमोबेश हासिल किए जा सकते हैं। कई बीमारियां प्रदूषित रक्त के जरिए फैलती हैं। हेपेटाइटिस की दोनों किस्में भी दूषित रक्त के जरिए विस्तार पाती हैं। हेपेटाइटिस बी लिवर के ऊतकों पर चोट करता है और कैंसर के जोखिम को बढ़ाता है। लक्षण और निदान पेचीदा हैं, लिहाजा वायरस कई सालों तक छिपा रह सकता है। वे दूसरों को प्रभावित करते हैं। लक्षण तब सामने आने लगते हैं, जब रोगाणु ज्यादा आक्रामक रुख अख्तियार कर लेते हैं। हालांकि हेपेटाइटिस की किस्मों का कोई इलाज नहीं है, लेकिन जो इलाज किया जाता है, उससे कुछ हद तक लक्षणों का बंदोबस्त किया जा सकता है। यानी इलाज से बीमारी कुछ सीमा तक काबू में की जा सकती है। हालांकि 2018 में नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम की शुरुआत की गई थी, जिसके तहत टेस्टिंग और दवाएं निःशुल्क हैं, लेकिन विश्व स्वास्थ्य संगठन की यह रपट भी है कि प्रोग्राम ज्यादातर मरीजों के पास पहुंचा ही नहीं है। बीते 20 सालों में खून की जांच के प्रोटोकॉल बहुत सख्त किए गए हैं, लिहाजा रक्त के संक्रमण का जोखिम कम हुआ है। भारत में हेपेटाइटिस बी संक्रमण मामलों का अभी तक जो विश्लेषण किए गए हैं, उनमें संक्रमण मां से शिशु की ओर गया है। टीकाकरण से भी इस बीमारी और संक्रमण के विस्तार को रोका जा सकता है। भारत में टीकाकरण भी काफी अनियमित है और शिशु के जन्म लेने के तुरंत बाद जो टीकाकरण किया जाना चाहिए, उसके प्रति अशिक्षित और अज्ञानी जमात गंभीर नहीं है, लिहाजा शिशु की इम्युनिटी प्रभावित होती है।

भारत में 50 फीसदी से कम शिशुओं को सभी आवश्यक टीके समयानुसार दिए जाते हैं। बहरहाल हेपेटाइटिस सी का इलाज अपेक्षाकृत आसान और संभव है। एंटी-वायरल बीमारी का इलाज कर सकते हैं और दीर्घकाल में लिवर को क्षतिग्रस्त होने से बचाया जा सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक, भारत में हेपेटाइटिस का उपलब्ध इलाज दुनिया में सबसे सस्ता है। करीब 70 फीसदी मरीज निदान और इलाज नेटवर्क से दूर भागते रहते हैं और प्राथमिक चिकित्सा को दोष देते रहते हैं। चूंकि यह चेतावनी विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से आई है, लिहाजा सरकारों के स्तर पर इस संक्रमण को संबोधित किया जाना चाहिए।

राय

आर्थिक पटरी पर मेले

पर्यटक सीजन में हिमाचली मेले एक बड़ी संभावना का आयोजन देख रहे हैं, लेकिन इस क्षमता को प्रदेश की आर्थिकी से जोड़ा ही नहीं गया। इसी तरह धार्मिक स्थलों की कमाई और आयोजनों को भविष्य की आर्थिकी नहीं माना गया। सुक्खू सरकार अगर व्यवस्था परिवर्तन के एहसास में पारंपरिक मेलों, धार्मिक आयोजनों, मंदिरों की आय तथा हिमाचल के लोक जीवन व कलाओं को आर्थिक पटरी पर रखे, तो आय के स्रोत खजाने को राहत दे सकते हैं। हिमाचल के हर गांव, कस्बे और शहर से जुड़ा कोई न कोई मेला है और इसी तरह धार्मिक स्थल भी वार्षिक रूप से धार्मिक मेलों की तरह योगदान दे रहे हैं। एक मोटे अनुमान के अनुसार तमाम मेलों के आयोजन में सरकारी गैरसरकारी व सामाजिक योगदान से करीब सौ करोड़ जुटाए जाते हैं और करीब इतनी ही आय विभिन्न मंदिरों से हो रही है। इस तरह दो सौ करोड़ के व्यय से मेले और मंदिर अपनी वार्षिक बजटीय व्यवस्था का निर्वहन कर रहे हैं, लेकिन आय-व्यय के हिसाब में न आगे बढने का संकल्प और न ही पारदर्शी नियम सामने आए हैं। इस रौनक में कुछ चेहरे वीआईपी नजर आते हैं, लेकिन वर्षों बाद भी परंपराओं के दूत कब्जा जमाए बैठे हैं। उदाहरण के लिए धर्मशाला के धुम्मू शाह मेले का आयोजन पुनः एक निरर्थक अभ्यास की तरह कई पाटों और हकदारों में विभक्त दिखाई दे रहा है। एक ओर प्रशासन तो दूसरी ओर सियासी निर्वाचन चुगली कर रहा है। मोटे तौर पर एक करोड़ के करीब आय की पहली खिडक़ी खुली है। यही मेला आय की दृष्टि से दस करोड़ का हो सकता है और इसी तरह हिमाचल का हर छोटा बड़ा मेला प्रेरित, परिष्कृत और वित्तीय रूप में अनुशासित किया जाए, तो आज सौ करोड़ कमा रहे मेले आगे चलकर हजार करोड़ के और इसी तरह मंदिरों की आय दस गुना बढ़ कर हजार करोड़ हो सकती है। इसके लिए योजना, अधोसंरचना तथ व्यवस्था का एक स्थायी ढांचा खड़ा करना पड़ेगा। मसलन हिमाचल में मेलों की क्षमता में स्थान व अतिक्रमण अवरोधक बना है। हर मेला स्थल को निश्चित जमीन तथा पार्किंग व ट्रैफिक प्लान चाहिए। कई मेले सडक़ों के किनारे होते आए हैं, जिन्हें अन्यत्र व्यवस्थित करना होगा। उदाहरण के लिए लिदबड़ (नगरोटा बगवां) मेले का स्तर सरकार ने बढ़ाया है, उसके आयोजन का स्थल अस्सी फीसदी घट चुका है। बड़े मेलों, यानी रेणुका जी, मंडी की शिवरात्रि, रामबुशहर की लवी, चंबा की मिंजर या सुजानपुर की होली की भी यही दिक्कत है कि आयोजन स्थल सिकुड़ रहे हैं, जबकि लोगों की रुचि से ये एक नए आयाम पर हैं। मेला विकास प्राधिकरण के तहत अगर मेलों का वर्गीकरण, मेला स्थलों का विकास, ट्रैफिक प्लान तथा पार्किंग व्यवस्था के समाधान करें, तो ये आयोजन पर्यटन की खूबसूरती में हिमाचली व्यंजनों, धाम तथा स्थानीय उत्पादों के बिक्री स्थल भी बन सकते हैं। इसी के साथ विभिन्न छिंजों को कुश्ती की प्रतिभा में समृद्ध कर सकते हैं। तमाम लोक व अन्य कलाकारों के साथ वार्षिक कान्ट्रेक्ट के तहत इन्हें स्थायी रोजगार दिया जा सकता है। इसी तरह के वार्षिक आयोजन हर मंदिर को लोक कला केंद्र के रूप में विकसित कर सकते हैं। मंदिरों की आय का व्यय सांस्कृतिक समारोहों, सभागारों, व्यवस्थित बाजारों व धर्म नगरियों के विकास तथा धार्मिक अनुष्ठान सामग्री व उपहार उद्योग को बढ़ावा देने के लिए करें, तो धार्मिक पर्यटन की क्षमता असीमित तौर पर बढ़ेगी। मंदिर आय से एक मंदिर रेल परियोजना शुरू की जा सकती है। कोंकण रेलवे की तर्ज पर भारत सरकार से 50:50 के अनुपात में यह परियोजना अंब अंदौरा से शुरू होकर चिंतपूर्णी, ज्वालाजी, कांगड़ा, चामुंडा, मंडी, हमीरपुर और बिलासपुर को जोड़ सकती है। मंदिर आय के सदुपयोग के लिए केंद्रीय मंदिर ट्रस्ट तथा मंदिर विकास प्राधिकरण का भी गठन करना होगा।

भूपिंदर सिंह

सिंथेटिक ट्रैक्स को तबाह मत करो

अभी भी समय है कि सरकार को चाहिए कि इन खेल मैदानों का रखरखाव ठीक ढंग से करवाए, ताकि हिमाचल प्रदेश के खिलाड़ी इन सुविधाओं का लंबे समय तक लाभ उठा सकें'

आज हिमाचल प्रदेश में बहुत संघर्ष के बाद बहुत अधिक धन व श्रम खर्च करके एथलेटिक्स के लिए विश्वस्तरीय प्ले फील्ड उपलब्ध है, मगर प्रशासन की खेलों के प्रति बेरुखी व अज्ञानता के कारण सब बरबाद होता जा रहा है। राज्य में तीन जगह सिंथेटिक ट्रैक बन कर तैयार हैं, मगर उन पर कहीं तो पार्क की तरह लोग सैर कर रहे हैं और कहीं पर जिला खेल अधिकारी व उपायुक्त फौज के हवाले कर कई दिनों के लिए भर्ती की स्वीकृति दे देते हैं। हमीरपुर का ट्रैक अब भारतीय खेल प्राधिकरण के पास है, मगर वहां भी हालत ठीक नहीं है। आजकल वहां मनोरंजन के लिए क्रिकेट देखने वालों के लिए बीच मैदान में स्क्रीन लगा दी है। जब क्रिकेट वाले अपने मैदानों में किसी को एक कदम भी नहीं रखने देते हैं, अच्छी बात है, मगर दूसरे की अंतरराष्ट्रीय प्ले फील्ड को बरबाद करना कहां तक सही है। सोचो राष्ट्रीय स्तर पर भाग लेने वाले हिमाचल के एथलीट पंद्रह दिन कहां ट्रेनिंग करेंगे। हिमाचल प्रदेश में खेल के साथ इस तरह की बदतमीजी आम बात हो गई है। करोड़ों रुपयों से बने सिंथेटिक ट्रैकों को हिमाचल प्रदेश के प्रशासनिक अधिकारी बरबाद करने पर क्यों आमादा हैं। क्या हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री व खेल मंत्री इस बात का संज्ञान लेंगे, ताकि इन अंतरराष्ट्रीय स्तर की खेल सुविधाओं को बचाया जा सके। प्रदेश के पास आज से दो दशक पहले तक खेल ढांचे के नाम पर सैंकड़ों साल पहले राजा-महाराजाओं द्वारा मेले व उत्सवों के लिए बनाए गए चंद, मगर बेहतरीन मैदान चंबा, मंडी, नादौन, सुजानपुर, जयसिंहपुर, कुल्लू, अनाडेल, रोहडू, रामपुर, सोलन, चैल, नाहन आदि जगहों पर थे।

इन मैदानों पर हिमाचल प्रदेश की खेल गतिविधियां कई दशकों से मेलों, उत्सवों व राजनीतिक रैलियों से बचे समय में चलती रही हैं। इन पुराने व ऐतिहासिक मैदानों का हाल कुछ ठीक नहीं है। कहीं अतिक्रमण व कहीं पर अव्यवस्था का बोलबाला साफ नजर आता है। वैसे तो हिमाचल प्रदेश की तरक्की में विभिन्न सरकारों का योगदान रहा है, मगर हिमाचल प्रदेश में पहली बार नई सदी के शुरुआती वर्षों में प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल की सरकार ने राज्य में अंतरराष्ट्रीय स्तर के खेल ढांचे को खड़ा करने की शुरुआत की और आज हिमाचल प्रदेश में कई खेलों के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्ले फील्ड एथलेटिक्स, क्रिकेट, हाकी, तैराकी व इंडोर खेलों के लिए उपलब्ध है। क्रिकेट में अनुराग ठाकुर की सोच ने हिमाचल प्रदेश को क्रिकेट के अंतरराष्ट्रीय मानचित्र पर लाकर खड़ा कर दिया है जो काबिले तारीफ है। लुहणू का खेल परिसर पूर्व मंत्री ठाकुर रामलाल के प्रयत्नों से बिलासपुर में सामने आया है। एथलेटिक्स सभी खेलों की जननी है। इसी से सब खेल निकले हैं और इसके प्रशिक्षण के बिना किसी खेल में दक्षता नहीं मिल सकती है। हिमाचल प्रदेश में आज हमीरपुर, बिलासपुर व धर्मशाला में तीन सिंथेटिक ट्रैक बन कर तैयार हैं। शिलारू के साई सैंटर में दो सौ मीटर का प्रैक्टिस ट्रैक बन कर तैयार है। सरस्वतीनगर में काम हो रहा है। किसी किसी राज्य के पास अभी तक एक भी ट्रैक नहीं है। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर व धर्मशाला सिंथेटिक ट्रैकों पर लोग टहलते नजर आते हैं। भर्ती के लिए बाहर कच्चे पर केवल ट्रायल के लिए स्वीकृत किया जा सकता है। शेष ट्रेनिंग बाहर के अन्य मैदानों व सडक़ों पर हो सकती है। सिंथेटिक ट्रैक पार्क बन चुके हैं। वहां आम लोगों का प्रवेश वर्जित कर देना चाहिए, केवल एथलीट के लिए ही प्रवेश रखना चाहिए।

तभी इन प्ले फील्ड को लंबे समय तक खिलाडियों के लिए उपलब्ध करवाया जा सकता है। कल जब हिमाचल प्रदेश के पास अंतरराष्ट्रीय स्तर के एथलीट होंगे और प्रशिक्षण के लिए उखड़ा हुआ ट्रैक होगा तो फिर पहाड़ की संतान को पिछडने का दंश झेलना पड़ेगा। इसलिए इस बरबादी को अभी से रोकना होगा। तभी हम अपनी आने वाली पीढियों से न्याय कर सकेंगे। इस कॉलम के माध्यम से इस विषय पर कई बार लिखने के बाद भी हिमाचल सरकार इन विश्व स्तरीय खेल सुविधाओं पर ध्यान नहीं दे रही है। हिमाचल में ट्रेनिंग कर पहाड़ की संतानें राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए कुछ लोगों के जुनून ने बिना सुविधाओं के मिट्टी पर ट्रेनिंग कर राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीत कर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दस्तक दी थी, तभी यह अंतरराष्ट्रीय स्तर की सुविधा आने वालों को मिल पाई हैं। हिमाचल प्रदेश में इस समय हर जिला स्तर सहित कई जगह उपमंडल स्तर पर भी इंडोर स्टेडियम बन कर तैयार हैं, मगर उन स्टेडियमों में बनी प्ले फील्ड का उपयोग प्रशिक्षण के लिए खिलाडियों को ठीक से करना नहीं मिल रहा है। वहां पर अधिकतर शहर के लाला व अधिकारी अपनी फिटनेस करते हैं। ऊना व मंडी में तरणताल बने हैं, मगर वहां पर भी कोई प्रशिक्षण कार्यक्रम आज तक शुरू नहीं हो पाया है। हिमाचल प्रदेश में तैराक ही नहीं हैं। यहां पर भी प्रशिक्षण न होकर गर्मियों में मस्ती जरूर हो जाती है। ऊना में हाकी के लिए एस्ट्रोटर्फ बिछी हुई है, मगर उसकी तो पहले ही दुर्गति हो गई है। हिमाचल प्रदेश सरकार का युवा सेवाएं एवं खेल विभाग अभी तक करोड़ों रुपए से बने इस खेल ढांचे के रखरखाव में नाकामयाब रहा है। उसके पास न तो चौकीदार हैं और न ही मैदान कर्मचारी, पर्याप्त प्रशिक्षकों की बात तो बहुत दूर की बात है।

नई खेल नीति में लिखा है कि सरकार विभिन्न खेल संघों, पूर्व खिलाडियों व प्रशिक्षकों से इन सुविधाओं का उपयोग कराने के लिए खेल अकादमियों का गठन कराएगी। अच्छे प्रशिक्षकों को खेल विभाग में कम से कम पांच वर्षों के लिए अनुबंधित करेगा या अन्य विभागों में नौकरी लगे पूर्व खिलाडियों व प्रशिक्षकों को प्रतिनियुक्ति पर लाकर या उन्हीं के विभाग में उन्हें खेल प्रबंधन व प्रशिक्षण देने का अधिकार देकर हिमाचल प्रदेश सरकार करोड़ों रुपए से बनी खेल सुविधाओं का सदुपयोग कर राज्य में खेलों को क्या गति नहीं दे सकती है? अभी भी समय है कि सरकार को चाहिए कि इन खेल मैदानों का रखरखाव ठीक ढंग से करवाए, ताकि हिमाचल प्रदेश के खिलाड़ी इन सुविधाओं का लंबे समय तक लाभ उठा सकें। राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर की ट्रेनिंग के लिए सिंथेटिक ट्रैक्स ही जरूरी हैं, मगर भर्ती व सैर के लिए और बहुत जगह हैं, इस बात को हमारे लोगों को समझना होगा। तभी खिलाडियों का कल्याण होगा।

सुरेश सेठ

जिसकी लाठी, उसकी भैंस

मेहता साहब सवेरे-सवेरे ही आए और बोले ''माफ करना शर्मा, मैंने तुमसे कल भला-बुरा कहा।'' मैं आश्चर्य के साथ बोला, ''क्या बात कर रहे हैं मेहता साहब, आपने मुझे कभी भला-बुरा नहीं कहा।'' ''तुम्हें याद नहीं है शर्मा, तुम भूल जाते हो। मैंने कल तुमसे बदतमीजी की थी। इसलिए भाई माफी मांगता हूं।'' ''चलो आपने भला-बुरा कहा भी होगा, लेकिन आप बड़े हैं, क्या हुआ अगर कह दिया तो। आप और मुझसे माफी मांगेंगे। ऐसा नहीं हो सकता।'' मैंने कहा तो मेहता जी बोले, ''अरे भाई हो रहा है। संसद में ही देख लो, पहले जानबूझ कर बदतमीजी करते हैं और बाद में माफी मांग लेते हैं।'' ''संसद की बात अलग है मेहता साब। वहां तो रोज ऐसा होता है। वहां बदतमीजों की क्या कमी है। आखिर उन्हें हमने ही तो चुनकर भेजा है। वे हमारे लिए लड़ते हैं, झगड़ते हैं। यहां तक कि दलगत राजनीति से प्रेरित होकर मनमुटाव तक कर लेते हैं। इसलिए हमारे लौकिक जीवन में बड़ा छोटे से माफी मांगे, शर्मसार करने वाली बात है।'' मैंने कहा तो मेहता साहब बोले, ''भाई शर्मा, मैं तो संसद का समाचार पढक़र दौड़ा चला आया। पता नहीं मैंने तुमसे कुछ गलत कह दिया हो। तुमने तो बुरा नहीं माना। लेकिन मैं भी इतना बुरा नहीं हूं कि माफी भी नहीं मांगू।'' ''आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। आजकल सब चलता है। माफी नहीं भी मांगते तो मैं आपका क्या बिगाड़ लेता। इसलिए इतना मत सोचा करो। नेताओं को देखो। अब तो गाली-गलौच संसद में मारा-पीटी तक करते हैं।

इतना अमर्यादित आचरण पहले कभी नहीं देखा। महिलाओं तक से बदतमीजी हो रही है।'' मैंने कहा तो मेहता साहब मूड़ में आ गए, बोले, ''शर्मा, चाय बनवाओ। विषय अच्छा है। इस पर बातचीत हो जाए, तो घण्टे दो घण्टे रविवार के आसानी से निकल जाएंगे।'' मैं सन्न रह गया। मुझे लगा मेहता साहब बदतमीजी पर उतर आए हैं। मुझे मॉर्निंग वॉक पर जाना था और उसके बाद पत्नी की दवा लेने। दोनों ही जरूरी काम ध्वस्त होने वाले थे। मैंने सोचा कि अब क्या किया जाए। मन ने कहा बदतमीजी, बदतमीजी को मारती है। इसलिए अब समय लिहाज छोडने का है। मैं बोला, ''मेहता साहब, यह समय तो मेरे मॉर्निंग वॉक का है। यह शाश्वत विषय है। इस पर फिर कभी सही।'' ''शर्मा कमाल कर दिया तुमने तो। बदतमीजी की हद होती है। तुमने तो औपचारिकता का भी परित्याग कर दिया है। मैंने बढक़र चाय की पेशकश की है और तुम मॉर्निंग वॉक का बहाना करके मुझे टरका रहे हो। एक दिन घूमने नहीं जाओगे तो शुगर नहीं बढ़ जाएगा। चलो पहले चाय बनवाओ।'' मेहता हठधर्मिता पर उतर आए थे। मैंने भी पैंतरा मारा, ''मेहता साहब, मैं चाय घूमने के बाद पीता हूं। आप माफी मांगने आए थे या मेरा खून पीने?'' मेहता साहब की आंखों से क्रोध की चिंगारियां निकलने लगी, वे चीखे, ''शर्मा मैं चाय पीकर जाऊंगा।'' मैं लगभग डर गया, तभी मेहता की चीख सुनकर पत्नी आ गई। आते ही बोली, ''क्यों क्या बात हुई मेहता साब? आप नाराज क्यों हो रहे हो?'' ''अरे मिसेज शर्मा, मामूली सी बात है।

मैंने कहा कि मैं चाय पीकर जाऊंगा और शर्मा कह रहा है कि उसका घूमने का वक्त हो गया। तनिक भी तमीज नहीं है इसे। मैंने आते ही अपनी बदतमीजी की माफी मांगी, लेकिन इसने सारे नियम-कायदे, छोटे-बड़े का लिहाज ताक में रखकर चाय की बात को टाले जा रहा है। तुम भी सुन लो मिसेज शर्मा, मैं चाय पिये बिना यहां से नहीं जाने वाला।'' मेहता जी का व्याख्यान सुनकर पत्नी ने मुझे और मैंने पत्नी को देखा। मुझे लगा यह जमाना जिसकी लाठी-उसकी भैंस का है। मजबूरन हमें चाय बनवानी पड़ी। बेमन से चाय पीकर उन्हें विदा किया। पत्नी बोली, ''मान न मान, मैं तेरा मेहमान। उलटा चोर कोतवाल को डांटे। अच्छी माफी मांगने आए थे।'' लेकिन हम विवश थे। उस दिन मैं घूमने भी नहीं गया और मेहता की बदतमीजी पर पूरे दिन सोचता रहा।

इनसाइड

150 रुपये गिरा सोने का भाव, क्या कीमतों और आएगी गिरावट?

ग्राम के स्तर पर आ गया। HDFC सिक्योरिटीज के मुताबिक, ग्लोबल मार्केट में महंगी धातुओं का भाव गिरा है, जिसका असर भारतीय बाजार पर भी दिखा।

पिछले कारोबारी सत्र में पीली धातु 70,050 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गई थी। इसने पहली बार 70 हजार रुपये का स्तर पार किया था। वहीं, चांदी की बात करें, तो इसमें 700 रुपये की गिरावट आई और यह 81,000 रुपये प्रति किलो के स्तर पर बंद हुई।

हालांकि, एक्सपर्ट का मानना है कि इस मामूली गिरावट के बावजूद सोने में तेजी का रुख बना रहेगा। LKP सिक्योरिटीज में रिसर्च एनालिस्ट जतिन त्रिवेदी का कहना है कि जब तक मध्यपूर्व में भू-राजनीतिक तनाव और ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदें बनी रहेंगी, तब तक सोने में तेजी का रुझान रहेगा।

दुनियाभर के केंद्रीय बैंक भी सोने की खरीद पर जोर दे रहे हैं, ताकि अचानक आने वाले आर्थिक संकट के नुकसान को कम से कम कर सकें। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास का भी कहना है कि रिजर्व बैंक अपने विदेशी मुद्रा भंडार को मजबूत करने के लिए सोने की खरीद बढ़ाएगा।

ऑफिशियल डेटा के मुताबिक, 22 मार्च को विदेशी मुद्रा भंडार में सोने की वैल्यू 51.48 अरब डॉलर थी। यह मार्च 2023 के मुकाबले 6.28 अरब डॉलर अधिक है।

महंगाई के मोर्चे पर राहत की खबर, मार्च में खुदरा महंगाई दर घटकर हुई 4.85 प्रतिशत

परिवहन विशेष न्यूज

मार्च महीने में खुदरा मुद्रास्फीति पांच महीने की निचले स्तर 4.85 प्रतिशत पर आ गई। सीपीआई आधारित खुदरा महंगाई फरवरी महीने में 5.09 प्रतिशत और मार्च 2023 में 5.66 प्रतिशत थी। अक्टूबर 2023 में सीपीआई आधारित मुद्रास्फीति की दर सबसे कम थी। तब यह 4.87 प्रतिशत पर थी। महंगाई का यह डेटा राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) द्वारा जारी किया जाता है।

नई दिल्ली। इस साल मार्च में खुदरा महंगाई दर 4.85 प्रतिशत के साथ नौ माह के निचले स्तर पर पहुंच गई। पिछले कुछ माह से खुदरा महंगाई में लगातार नरमी का रुख है। इससे पहले फरवरी माह में खुदरा महंगाई दर 5.09 प्रतिशत थी।

आरबीआई ने अप्रैल से शुरू होने वाले नए वित्त वर्ष 2024-25 में खुदरा महंगाई दर पांच प्रतिशत से नीचे रहने का अनुमान लगाया है। आने वाले महीनों में खुदरा महंगाई दर और कम हो सकती है।हालांकि मार्च में खाद्य वस्तुओं की महंगाई दर 8.52 प्रतिशत रही जो फरवरी की 8.66 प्रतिशत से मामूली कम है।

महंगे हुए खाद्य पदार्थ

मार्च में सब्जी, दाल, मसाले, अंडे जैसी खाद्य वस्तुओं की कीमतों में दहाई अंक में बढ़ोतरी दर्ज की गई। सिर्फ खाद्य तेल व वनस्पति के खुदरा दाम में पिछले साल मार्च की तुलना में 11.72 प्रतिशत की गिरावट देखी गई।

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक मार्च में सब्जी के दाम में पिछले साल मार्च के मुकाबले 28.34 प्रतिशत, अंडे में 10.33 प्रतिशत, दाल व दलहन में 17.71 प्रतिशत तो मसाले के भाव में 11.40 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई। अनाज के दाम में यह बढ़ोतरी 8.37 प्रतिशत की रही।

गैर खाद्य पदार्थ भी महंगे

गैर खाद्य पदार्थों में कपड़े व फुटवियर के खुदरा दाम में 2.97 प्रतिशत, स्वास्थ्य में 4.34 प्रतिशत तो ट्रांसपोर्ट व संचार की कीमतों में 1.52 प्रतिशत का इजाफा रहा। लेकिन ईंधन व बिजली की खुदरा कीमतों में पिछले साल मार्च की तुलना में 3.24 प्रतिशत की गिरावट रही।

औद्योगिक उत्पादन में तेजी

फरवरी के औद्योगिक उत्पादन में 5.7 प्रतिशत की बढ़ोतरीगत फरवरी माह के औद्योगिक उत्पादन में पिछले साल फरवरी की तुलना में 5.7 प्रतिशत की बढ़ोतरी रही। इस अवधि में मैन्यूफैक्चरिंग में पांच प्रतिशत का इजाफा रहा जो अर्थव्यवस्था में मांग की मजबूती को दर्शाता है।

मैन्यूफैक्चरिंग बढ़ने से रोजगार में भी बढ़ोतरी होती है। हालांकि फरवरी में कैपिटल गुड्स में सिर्फ 1.2 प्रतिशत का इजाफा रहा। कैपिटल गुड्स में बढ़ोतरी मुख्य रूप से भविष्य में मैन्यूफैक्चरिंग में होने वाले विस्तार को दर्शाता है।

नॉन ड्यूरेबल गुड्स में गिरावट

आंकड़ों के मुताबिक, इस साल फरवरी में खनन के उत्पादन में आठ प्रतिशत, बिजली में 7.5 प्रतिशत, प्राइमरी गुड्स में 5.9 प्रतिशत, इंटरमीडिएट गुड्स में 9.5 प्रतिशत, इंफ्रास्ट्रक्चर गुड्स में 8.5 प्रतिशत, तो कंज्यूमर ड्यूरेबल में 12.3 प्रतिशत की बढ़ोतरी रही। कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल गुड्स में इस अवधि में 3.8 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई।

इस नए ऐप के जरिए फिनटेक मार्केट में एंट्री लेंगे अशनीर ग्रोवर, जानिए क्या है खास

भारत पे के को फाउंडर अब एक नई ऐप के साथ फिनटेक मार्केट में प्रवेश कर रहे हैं। इस ऐप को जीरो पे नाम दिया गया है जो एक मेडिकल लोन ऐप है। फिलहाल ये ऐप अभी टेस्टिंग फेज में है और इसे थर्ड यूनिकॉर्न द्वारा विकसित किया गया है। थर्ड यूनिकॉर्न की स्थापना ग्रोवर ने भारतपे से बाहर निकलने के बाद की थी।

नई दिल्ली। अपनी अगली पारी की तैयारी करते हुए भारतपे के को फाउंडर और फॉर्मर मैनेजिंग डॉयरेक्टर अशनीर ग्रोवर ने जीरोपे नामक मेडिकल लोन ऐप के साथ फिनटेक क्षेत्र में एंट्री लेने की योजना बनाई है।

लिस्टिंग से पता चला है कि ZeroPe फिलहाल अभी भी टेस्टिंग मोड में है और इसे थर्ड यूनिकॉर्न द्वारा विकसित किया गया है। आइये इसके बारे में जानते हैं।

ZeroPe क्या है?

जैसा कि हम बता चुके हैं कि ZeroPe को थर्ड यूनिकॉर्न द्वारा विकसित किया गया है। इसकी स्थापना ग्रोवर ने भारतपे से बाहर निकलने के बाद की थी और 2023 में क्रिकपे नामक एक फेंटसी गेमिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था।

आपको बता दें कि जीरोपे ऐप दिल्ली स्थित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (NBFC) मुकुट फिनवेस्ट के साथ साझेदारी में 5 लाख रुपये तक के तत्काल प्री-अप्रूव्ड मेडिकल लोन की सुविधा देगा।

ZeroPe ऐप वेबसाइट का कहना है कि इस सेवा का लाभ केवल भागीदारी वाले अस्पतालों में ही उठाया जा सकता है।

ग्रोवर सेवइन, क्यूब हेल्थ, आरोग्य फाइनेंस, नियोडॉक्स, फाइब, केंको और मायकरे हेल्थ जैसे व्यवसायों की बढ़ती सीरीज में नए स्तर पर प्रवेश कर रहे हैं।

यह आपको चिकित्सा बिलों और अन्य वैकल्पिक उपचारों के लिए इस्टेंट फाइनेंसिंग सॉल्यूशन देता है।

कब शुरू हुई थी कंपनी

आपको बता दें कि ग्रोवर ने जनवरी 2023 में अपनी पत्नी माधुरी जैन ग्रोवर और चंडीगढ़ स्थित एटरप्रेन्योर असीम घावरी के साथ थर्ड यूनिकॉर्न लॉन्च किया।

ये स्टार्टअप ड्रीम11, मोबाइल प्रीमियर लीग (एमपीएल) और गेम्स24x7 के माय11सर्कल जैसे प्रतिद्वंद्वियों को टक्कर देने के लिए क्रिकपे को लेकर आया है।

एक रिपोर्ट में पता चला है कि भारत का डिजिटल हेल्थकेयर बाजार 2030 तक 37 बिलियन डॉलर का राजस्व जनरेट कर सकता है। इसमें से अकेले हेल्थकेयर फाइनेंस 5 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है।

ग्राउंड हैंडलिंग सर्विसेज के लिए नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने बर्ड ग्रुप का किया चयन

नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा ने बताया कि जेवर पर बनने वाले हवाई अड्डे पर ग्राउंड-हैंडलिंग सॉल्यूशन और सेवाएं देने के लिए उसने बर्ड ग्रुप के साथ साझेदारी की है। मझौते के तहत बर्ड ग्रुप ग्राउंड हैंडलिंग परियोजना के लिए व्यापक जिम्मेदारियां संभालेगा। इसमें यात्रियों के अनुभव को बढ़ाने के उद्देश्य से सेवाओं का समूह शामिल है।हर यात्री के लिए गर्मजोशी से स्वागत और सुचारू रैंप संचालन का सचालन शामिल है।

नई दिल्ली। नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे ने शुक्रवार को कहा कि उसने उत्तर प्रदेश के जेवर में बनने वाले हवाई अड्डे पर ग्राउंड-हैंडलिंग सॉल्यूशन और सेवाएं देने के लिए बर्ड ग्रुप के साथ एक रियायत समझौता किया है। हवाई अड्डे ने कहा कि रणनीतिक साझेदारी हवाई अड्डे पर कुशल और निर्बाध ग्राउंड-हैंडलिंग गतिविधियों को सुनिश्चित करेगी, जिससे समग्र यात्री अनुभव में वृद्धि होगी।

ग्रीनफील्ड परियोजना

अधिकारियों के अनुसार, ग्रीनफील्ड परियोजना दिल्ली से 75 किमी दूर यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे स्थित है और इस साल के अंत तक विकास के पहले चरण के बाद कमर्शियल सेवाओं के लिए खुलने की उम्मीद है। एक रनवे और एक टर्मिनल वाले हवाई अड्डे के पहले चरण में सालाना 12 मिलियन यात्रियों के यातायात को संभालने की क्षमता होगी। उन्होंने कहा कि सभी चार विकास चरणों के पूरा होने पर, हवाईअड्डा प्रति वर्ष 70 मिलियन यात्रियों को सेवा देने में सक्षम होगा।

बर्ड ग्रुप संभालेगा जिम्मेदारियां

समझौते के तहत, बर्ड ग्रुप ग्राउंड हैंडलिंग परियोजना के लिए व्यापक जिम्मेदारियां संभालेगा। इसमें यात्रियों के अनुभव को बढ़ाने के उद्देश्य से सेवाओं का एक व्यापक समूह शामिल है। इसमें प्रत्येक यात्री के लिए गर्मजोशी से स्वागत सुनिश्चित करने से लेकर सुचारू रैंप संचालन और सामान पर सावधानीपूर्वक ध्यान देने तक सब कुछ शामिल है।

वर्ष 2034 तक शहरों में होगी 7.8 करोड़ मकान की जरूरत

इस अवधि तक 1.5 ट्रिलियन डॉलर हो जाएगा रियल एस्टेट बाजार

भारतीय अर्थव्यवस्था के आकार में बढ़ोतरी से रियल एस्टेट सेक्टर को फायदा होता दिख रहा है। औद्योगिक संगठन सीआईआई और नाइट फ्रैंक की रिपोर्ट के मुताबिक अगले दस सालों में भारत की आबादी में बढ़ोतरी और शहर में लोगों के पलायन से 7.8 करोड़ मकान की जरूरत होगी। आवासीय मकान के साथ ऑफिस के लिए जगह मैन्युफैक्चरिंग के लिए जमीन और वेयरहाउस की भी मांग में बढ़ोतरी होगी।

नई दिल्ली। भारतीय अर्थव्यवस्था के आकार में बढ़ोतरी से रियल एस्टेट सेक्टर को फायदा होता दिख रहा है। औद्योगिक संगठन सीआईआई और नाइट फ्रैंक की रिपोर्ट के मुताबिक अगले दस सालों में भारत की आबादी में बढ़ोतरी और शहर में लोगों के पलायन से 7.8 करोड़ मकान की जरूरत होगी।

आवासीय मकान के साथ ऑफिस के लिए जगह, मैन्युफैक्चरिंग के लिए जमीन और वेयरहाउस की भी मांग में बढ़ोतरी होगी। रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2034 तक भारत के जीडीपी का आकार 10.3 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच सकता है और इस अवधि तक 1.5 ट्रिलियन डॉलर के बाजार आकार के साथ जीडीपी में रियल एस्टेट की हिस्सेदारी 10.5 प्रतिशत हो जाएगी।

वर्ष 2023 में रियल एस्टेट बाजार का आकार 482 अरब डॉलर का था। रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2034 तक देश की आबादी 1.55 अरब पहुंचने की उम्मीद है और इस अवधि तक अनुमान के मुताबिक 42.5 प्रतिशत लोग शहर में रहने लगेंगे। इतनी बड़ी मांग को पूरा करने के लिए अतिरिक्त रूप से 7.8 करोड़ मकान की जरूरत होगी।

टियर-2 और टियर-3 शहरों में भी होगा तेजी से विकास वर्ष 2034 तक रियल एस्टेट के आवासीय सेक्टर का बाजार आकार 906 अरब डॉलर तो आफिस सेक्टर का बाजार आकार 125 अरब डॉलर का हो जाएगा।

भारत में आर्थिक गतिविधियों के विकास को देखते हुए वर्ष 2034 तक ऑफिस के लिए 2.7 अरब वर्ग फुट जगह की जरूरत होगी। टियर-2 व टियर-3 शहरों में भी रियल एस्टेट सेक्टर का तेजी से विकास होगा।

प्रोपटाइगरडाटकॉम के मुताबिक इस साल जनवरी-मार्च में देश के आठ बड़े शहरों में मकानों की बिक्री में पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 68 प्रतिशत की बढ़ोतरी रही। इस साल आठ बड़े शहरों में 1.10 लाख करोड़ मूल्य के मकान की बिक्री हुई जबकि पिछले साल जनवरी-मार्च में यह बिक्री 66,155 करोड़ रुपये की थी।

सीआईआई से जुड़ी रियल एस्टेट कमेटी के प्रेसिडेंट नील रहेजा का कहना है कि सरकार की नीति, टेक्नोलॉजी के विस्तार एवं बड़ी संख्या में शहरों की ओर पलायन से रियल एस्टेट सेक्टर अगले दस सालों तक तेजी से बढ़ेगा।

2.98 अरब अमेरिकी डॉलर बढ़ा विदेशी मुद्रा भंडार, पहुंचा अब तक का उच्चतम स्तर पर...

विदेशी मुद्रा भंडार 2 .98 अरब अमेरिकी डॉलर उछलकर 648 .562 अरब अमेरिकी डॉलर की नई ऊंचाई पर पहुंच गया। सितंबर 2021 में देश की विदेशी मुद्रा किटी 642 .453 बिलियन अमेरिकी डॉलर के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गई जो इस साल मार्च में टूट गया था। इसके साथ ही सोने का भंडार 2 .398 बिलियन अमेरिकी डॉलर बढ़कर 54 .558 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया।

मुंबई। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 5 अप्रैल को समाप्त सप्ताह में 2.98 बिलियन अमेरिकी डॉलर बढ़कर 648.562 बिलियन अमेरिकी डॉलर के नए शिखर पर पहुंच गया, आरबीआई ने शुक्रवार को कहा। पिछले रिपोर्टिंग सप्ताह में, विदेशी मुद्रा भंडार 2.951 बिलियन अमेरिकी डॉलर बढ़कर 645.583 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया था, जो अब तक का उच्चतम स्तर था। सितंबर 2021 में, देश की विदेशी मुद्रा किटी 642.453 बिलियन अमेरिकी डॉलर के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गई, जो इस साल मार्च में टूट गया था।

विदेशी मुद्रा भंडार में लगातार वृद्धि

वैश्विक घटनाओं के कारण बने दबावों के बीच केंद्रीय बैंक द्वारा रुपये की रक्षा के लिए भंडार तैनात किए जाने से भंडार पर असर पड़ा, लेकिन पिछले कुछ महीनों में इसमें लगातार वृद्धि हुई है।

शुक्रवार को जारी आंकड़ों के अनुसार, 5 अप्रैल को समाप्त सप्ताह के लिए विदेशी मुद्रा संपत्ति 549 मिलियन अमेरिकी डॉलर बढ़कर 571.166 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया।

डॉलर के संदर्भ में व्यक्त, विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों में विदेशी मुद्रा भंडार में रखे गए यूरो, पाउंड और येन जैसी गैर-अमेरिकी इकाइयों की सराहना या मूल्यह्रास का प्रभाव शामिल होता है।

सोने का भंडार में बढ़ोतरी

आरबीआई ने कहा कि सप्ताह के दौरान सोने का भंडार 2.398 बिलियन अमेरिकी डॉलर बढ़कर 54.558 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया।

शीर्ष बैंक ने कहा कि विशेष आहरण अधिकार (एसडीआर) 24 मिलियन अमेरिकी डॉलर बढ़कर 18.17 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गए।

शीर्ष बैंक के आंकड़ों से पता चलता है कि समीक्षाधीन सप्ताह में आईएमएफ के साथ भारत की आरक्षित स्थिति भी 9 मिलियन अमेरिकी डॉलर बढ़कर 4.669 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गई।

गर्मी की छुट्टियों में क्या कंफर्म होगी आपकी ट्रेन टिकट? यह Code दूर कर देगा सारी कंफ्यूजन

गर्मी की छुट्टियां शुरू होने वाली है। ऐसे में लोग धड़ाधड़ ट्रेन की टिकट पर बुक कर रहे हैं। कई लोग वेटिंग टिकट ले लेते हैं और कंफर्म होने का इंतजार करते हैं। अगर पहले से ही यात्री को पता चल जाए कि टिकट कंफर्म होने की संभावना क्या है तो यह काफी अच्छा होगा। आइए जानते हैं कि किस टिकट कोड में टिकट कंफर्म के चांस ज्यादा है।

नई दिल्ली। गर्मी की छुट्टियों में भी ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों की मारामारी रहती है। कंफर्म के साथ वेटिंग टिकट वाले भी ट्रेन में सफर करते हैं। हालांकि, भीड़ को कंट्रोल करने के लिए भारतीय रेलवे द्वारा कई स्पेशल ट्रेनें चलाई जाती है।

ट्रेन की टिकट जब बुक की जाती है तो उस पर कोड आता है। हम उन कोड को नजरअंदाज कर देते हैं। वैसे तो वो कोड बड़े काम का है। दरअसल, उस कोड से आसानी से जाना जा सकता है कि टिकट कंफर्म होने की क्या संभावना है। चलिए, आज हम आपको उन कोड के बारे में बताते हैं।

कितने तरह की होती है वेटिंग टिकट

भारतीय रेलवे कई तरह की वेटिंग टिकट जारी करती है। इसके बारे में कई यात्रियों को पता नहीं होता है। अगर आप वेटिंग टिकट को ध्यान से देखें तो उस GNWL, RLWL, PQWL, RLGN, RSWL इनमें से कोई एक कोड लिखा होगा। इस कोड के जरिये आप जान सकते हैं कि टिकट कंफर्म होने की संभावना कितनी है।

GNWL का अर्थ जनरल वेटिंग लिस्ट होती है। इसे वेटिंग टिकट के वक्त जारी किया जाता है। यह टिकट जब आप ओरिजनल स्टेशन से सफर करते हैं तब मिलती है। उदाहरण के तौर पर अगर आप दिल्ली से बनारस के लिए सफर कर रहे हैं और दिल्ली से टिकट लेते हैं तब आपको यह टिकट मिलता है। अगर आप गाजियाबाद से सफर शुरू करेंगे तब आपको यह टिकट नहीं मिलेगा।

रेपो रेट में बदलाव न होने का रियल एस्टेट सेक्टर ने किया स्वागत, डेवलपर्स ने कहा- आरबीआई के फैसले से मिलेगा बूस्ट

एयरपोर्ट पर अक्सर तस्करी का सोना (Gold Smuggling) बरामद होने की खबर आती है। कई बार तस्कर पेट या फिर मलाशय जैसी संवेदनशील जैसी जगहों पर भी गोल्ड छिपाकर लाते हैं। हर मामले में गोल्ड छिपाने का तरीका अलग-अलग हो सकता है। लेकिन मामला हर बार दुबई से गोल्ड लाने का ही होता है। आइए जानते हैं दुबई से सबसे ज्यादा गोल्ड स्मगल होने की वजह।

नई दिल्ली। पिछले दिनों पहले मुंबई एयरपोर्ट पर एक महिला यात्री सैंडल में 24 कैरेट की 2 गोल्ड चैन छिपाकर लाते हुए पकड़ी गई। उससे पहले कस्टम अधिकारियों ने एक यात्री को अमूल मक्खन में छिपाकर सोने की तस्करी करते हुए पकड़ा था।

पिछले साल अक्टूबर में कस्टम अधिकारियों को एक विमान यात्री पर शक हुआ। तलाशी में कुछ नहीं मिला। लेकिन, एक्सरे में पता चला कि उसके मलाशय में 600 ग्राम से अधिक का गोल्ड पेस्ट है। उस वक्त उसकी कीमत करीब 37 लाख रुपये थी। उससे करीब एक महीने पहले एक यात्री मलाशय में 840 ग्राम सोने के साथ पकड़ा गया था।

इस तरह की खबरें अक्सर आती रहती हैं। हर मामले में गोल्ड छिपाने का तरीका अलग-अलग हो सकता है। लेकिन, एक चीज अक्सर कॉमन रहती है, वो है किस जगह से सोना लाया जा रहा है। 100 में से 100 दफा मामला दुबई का ही होता है।

अब सवाल उठता है कि दुबई के सोने में ऐसी क्या खासियत है, जिसके लिए लोग कानून तोड़ने के साथ ही अपनी जान पर खेलने में भी तनिक संकोच नहीं करते। आइए इसका जवाब जानते हैं।

गोल्ड की कीमतों में है बड़ा अंतर

शुक्रवार यानी 12 अप्रैल की बात करें, तो भारत में 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 75 हजार रुपये से अधिक था। लेकिन, दुबई में आपको 10 ग्राम सोने के लिए करीब 65 हजार रुपये ही चुकाने होंगे। मतलब कि 10 ग्राम सोने पर ही 10 हजार रुपये का सीधे-सीधे फायदा।

अगर सोने का वजन बढ़ाकर 100 ग्राम करें, तो दोनों देशों की कीमतों में फर्क 1 लाख रुपये तक पहुंच जाएगा। और यह फर्क दुबई से भारत में गोल्ड स्मगलिंग बढ़ने की एक बड़ी वजह है।

लाजवाब क्वॉलिटी और डिजाइन

दुबई के सोने की क्वॉलिटी को दूसरे मुल्कों के मुकाबले काफी बेहतर माना जाता है। साथ ही, वहां सोने पर काम भी काफी बारीकी से होता है। ऐसे-ऐसे डिजाइन होते हैं कि नजर ही न हटे। अगर स्मगलरों को दुबई के सोने की क्वॉलिटी लुभाती है, तो आम लोगों को डिजाइन। कई बार दुबई के 22 कैरेट गोल्ड को भारत जैसे बाजारों में 24 कैरेट गोल्ड बताकर भी बेच दिया जाता है।

कौन लोग लाते हैं दुबई से गोल्ड

भारत में बहुत से लोग दुबई में रोजगार करते हैं और वही सबसे ज्यादा गोल्ड भी लाते हैं। ज्यादातर लोग सोना कानूनी तरीके से ही लाते हैं। लेकिन, कुछ गैरकानूनी रास्ता अपनाते हैं। इनमें से अधिकतर कामगार होते हैं, जो मजदूरी की तलाश में दुबई गए होते हैं।

दरअसल, स्मगलरों को इस तरह के लोगों की तलाश रहती है। कई बार एयरपोर्ट पर लोग अपने पेट या फिर प्राइवेट में भी गोल्ड लाते हुए पकड़े गए हैं। यह ना सिर्फ गैरकानूनी है, बल्कि इससे उनकी जान जाने का भी जोखिम रहता है।

दुबई से कितना सोना ला सकते हैं?

अगर कानूनी तरीके की बात करें, तो एक साल दुबई में रहने वाले पुरुष अधिकतम 20 ग्राम सोना ला सकते हैं, लेकिन उसका मूल्य 50 हजार रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए। वहीं, महिलाओं के मामले में यह छूट 40 ग्राम और 1 लाख रुपये तक है। इससे अधिक सोना लाने की सूरत में आपको कस्टम ड्यूटी चुकानी होगी।

जेल में सीएम पर 7 सांसदों की दूरी से आप में बेचैनी

परिवहन विशेष। एसडी सेठी।

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी के मुखिया और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जेल बंदी के बावजूद उसके 9 सांसदों में से 7 सांसदों की अब तक दूरी बनाए रखने से आप पार्टी में बेचैनी होने लगी है। आप के बिग शॉट राघव चड्ढा,स्वाति मॉलीवाल, किक्रेटर हरभजन सिंह की गैरहाजिरी के चलते दिल्ली में चल रहे विरोध प्रदर्शनों में खासी कमी खल रही है। इनको मिलाकर 7 सांसद इस दौरान पटल पर से गायब दिख रहे है। इससे जाहिर है कि आम आदमी पार्टी के लिए खतरे के संकेत उभरने लगे हैं। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से ही पार्टी में हलचल बढती जा रही है। बता दें कि पहले पंजाब से इकलौते लोकसभा सांसद सुशील कुमार टिक्कू ने पार्टी छोडकर बीजेपी जॉइन कर ली थी। उनके साथ आप विधायक भी बीजेपी में शामिल हुआ था।अब जैसी हालत बनती दिख रही है उससे से तो यही लगता है कि पूरी पार्टी ही संकट के दौर में है। आम आदमी पार्टी के करीब 7 सांसदो ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से जो दूरी बनाई वह रहस्यमय है। इनके तर्क किसी के गले नहीं उतर रहे हैं। राघव चड्ढा इंग्लैंड में स्टे हैं। वह अपनी आंख का इलाज करवा रहे हैं। वही स्वाती मॉलीवाल अमेरीका में है।, किक्रेट हरभजन सिंह अपनी कमेंट्री में बीजी है। वहीं मंत्री राजकुमार आनंद ने मंत्री पद समेत आप की सदस्यता तक से पिंड छुडा लिया।इसके बावजूद आप के सिपहसलारों का आरोप है कि केंद्र सरकार लगातार आम आदमी पार्टी को तोडने का प्रयास कर रही है। दरअसल जेल में बंद सीएम और पार्टी संयोजक को पार्टी के टूटने का डर सता रहा है। वहीं संजय सिंह ने गायब सांसदों के रवैये की बावत कहां कि पार्टी अपने मंच पर इसकी चर्चा करेगी।

दिल्ली में राष्ट्रपति शासन के लिए एलजी ने गृह मंत्रालय को लिखी चिट्ठी

एलजी की शिकायत है कि उन्होंने तमाम मंत्री जिनमें सौरभ भारद्वाज, गोपाल राय,कैलाश गहलोत,और आतिशी समेत सभी मंत्रियों को बैठक में बुलाने के बावजूद वह नहीं आ रहे हैं।

परिवहन विशेष न्यूज

एसडी सेठी। दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार पर एक के बाद एक जबरदस्त झटका लग रहा है। अब एलजी वीके सक्सेना ने गृह मंत्रालय को पत्र लिखकर दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए पत्र लिखा है। इससे पहले अरविंद केजरीवाल समेत दो चोटी के मंत्री, और एक सांसद जेल की सलाखो के पीछे जा चुके हैं। इसके बाद दिल्ली के एक मंत्री राजकुमार आनंद ने तो पार्टी को भ्रष्टाचार के दलदल में डूबी तक पार्टी को बताकर मंत्री पद से लेकर पार्टी की सदस्यता तक से अपना पिंड छुडा लिया है। आप के 9 सांसद तक सीएम केजरीवाल के जेल पहुंचने के बावजूद सामने नहीं आए हैं। इनमें राघव चड्ढा,एनडी गुप्ता,स्वाति मॉलीवाल,क्रिकेटर सांसद हरभजन सिंह,समेत प्रमुख नाम है। इसके बाद आम आदमी पार्टी को एक और बडा झटका, दिल्ली में राष्ट्रपति शासन के लिए उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने गृह मंत्रालय को पत्र लिख दिया है। एलजी की शिकायत है कि उन्होंने तमाम मंत्री जिनमें सौरभ भारद्वाज, गोपाल राय,कैलाश गहलोत,और आतिशी समेत सभी मंत्रियों को बैठक में बुलाने के बावजूद वह नहीं आ रहे हैं। एलजी ने पत्र में यह भी लिखा कि आप के नेताओ ने भी उन्हें चुनौती देते हुए कहा कि 'हिम्मत है तो दिल्ली में राष्ट्रपति लगा कर दिखाए'। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से ही दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने की अटकलें तेज हैं।

एलजी वीके सक्सेना की ताजा चिट्ठी लिखने के बाद आम आदमी पार्टी की घबराहट और ज्यादा बढ गई है। दरअसल एलजी और दिल्ली सरकार के बीच टकराव दिन-ब-दिन बढता जा रहा है।दिल्ली में तमाम विकास कार्य रूक गए हैं। उधर एलजी वीके सक्सेना का दर्द है कि मंत्रियो ने आचार संहिता लागू होने का हवाला देकर बैठक में आने से मना कर दिया है। उल्लेखनीय है कि दिल्ली सरकार और एलजी के बीच टकराव काफी समय से है। पिछले 8 सालों में 3 एलजी रह चुके है। इस बीच तमाम अदालती आदेश आए लेकिन विवाद नहीं थम पाया। आप की सरकार से टकराव की शुरूआत नजीब जंग के एलजी रहते हुई थी।फिर एलजी बने अनिल बैजल,टकराव यहां भी बादस्तूर जारी रहा। अब वीके सक्सेना के एलजी रहते टकराव में और इजाफा ही हुआ है। टकराव का आलम ये है कि दोनों में पॉवर का खेला है। मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी गया।एलजी ने ही कथित शराब नीति घोटाले की सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। इसी मामले में आम आदमी पार्टी के मुख्य चेहरे सीएम अरविंद केजरीवाल, डिप्टी सीएम मनीष सिसौदिया,समेत संजय सिंह,तक जेल की सलाखों के पीछे जा चुके है। अब कथित शराब घोटाले के तार साऊथ इंडिया तक पहुंच गए हैं।के.कविता को भी शुक्रवार को सीबीआई ने 15 अप्रैल तक रिमांड पर कोर्ट से ले लिया है।बहरहाल सीएम केजरीवाल को 14 अप्रैल को कोर्ट में पेश किया जाएगा। कयास लगाए जा रहे हैं कि इससे पहले ही एलजी के गृह मंत्रालय को लिखे पत्र पर फैंसला हो सकता है।

लुटियंस दिल्ली में भी नजर आएगा घंटाघर, एलजी वीके सक्सेना के निर्देश पर ढूंढी जा रही उपयुक्त जगह

परिवहन विशेष न्यूज

एनडीएमसी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि हम एलजी वीके सक्सेना के निर्देश पर जगह ढूंढ रहे हैं लेकिन अभी इस पर कोई अंतिम निर्णय नहीं हो पाया है। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (एनडीएमसी) का मुख्यालय पालिका केंद्र जहां हैं वहां पर पहले नई दिल्ली टाउन हॉल नाम से एक इमारत एनडीसीसी फेज -2 की जगह हुआ करती थी।

नई दिल्ली। 1980 से पहले जिस प्रकार से नई दिल्ली टाउन हॉल में घंटाघर हुआ करता था, वैसा ही घंटाघर अब लुटियंस दिल्ली में नजर आएगा। हालांकि यह कहां होगा, अभी इसके लिए स्थान चिह्नित नहीं हुआ है, लेकिन उपराज्यपाल वीके सक्सेना के निर्देश पर एनडीएमसी उस उपयुक्त जगह को ढूंढने में लगी है।

संभवतः यह स्थान कनॉट प्लेस या इसके आस-पास के इलाकों में ही हो सकता है। जहां पर आसानी से रोड से गुजरने वाले लोगों को वह घंटाघर समय बताएगा। एनडीएमसी की कोशिश हैं कि ऐसे स्थान पर यह घंटाघर बनाया जाए जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग इससे समय देख सकें।

एलजी सक्सेना घंटे के लिए ढूंढ़ रहे जगह

एनडीएमसी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि हम एलजी वीके सक्सेना के निर्देश पर जगह ढूंढ रहे हैं, लेकिन अभी इस पर कोई अंतिम निर्णय नहीं हो पाया है। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (एनडीएमसी) का मुख्यालय पालिका केंद्र जहां हैं वहां पर पहले नई दिल्ली टाउन हॉल नाम से एक इमारत एनडीसीसी फेज -2 की जगह हुआ करती थी।

ब्रिटेन की रेलवे कंपनी ने इन घंटों का किया था निर्माण

1933 में वह इमारत बनी थी। जिसमें ऊपर घंटाघर बना हुआ था, जिसमें 4 भारी भरकम घंटे भी लटके हुए थे। यह घंटे ब्रिटेन से उस समय की इम्पीरियल मुनिसिपलिटी ने मंगाए थे। ब्रिटेन की रेलवे कंपनी ने इन घंटों का निर्माण किया था। उस समय इन घंटों को हर घंटे के अंतराल पर समय से बजाया जाता था। बकायदा इसके लिए उस समय मुनिसिपलिटी में कर्मचारी भी रखे जाते थे। जो दिन में हर घंटे अनुसार घंटे बजाकर नागरिकों को समय से अवगत कराते थे।

नई दिल्ली टाउन हॉल को तोड़कर जब जब नया मुख्यालय पालिका केंद्र की इमारत को 1982 में बना दिया गया तो शिवाजी स्टेडियम के पुनर्विकास के बाद टाउन हाल की घड़ी को वहां मैग्जीन मार्केट के ऊपर लगा दिया गया। राष्ट्रमंडल खेलों के दौरान फिर शिवाजी स्टेडियम का पुनर्निर्माण हुआ तो यह घड़ी यहां से गायब हो गई।

4 घंटे टाउन हॉस में लगाए गए थे

पालिका केंद्र बना तो जो 4 घंटे टाउन हॉल में लगाए गए थे तो उन्हें पालिका मुख्यालय के प्रवेश द्वारा पर अंदर ही इमारत में लटका दिया गया, लेकिन यह घंटे इतने भारी थे कि एक दिन गिर गए और इनमें से 2 टूट भी गए। जिन्हें एनडीएमसी ने उठाकर मुख्यालय के अंदर ही रिसेप्शन के पास बरामदे में पारदर्शी फ्रेम में रखा हुआ है। इनके स्थान पर एनडीएमसी ने अब हल्की फैंसी घण्टियां लटका रखी हैं। अधिकारी ने बताया कि भले ही आज का समय स्मार्ट घड़ियों का है और शहर भी चाहे कितने ही स्मार्ट हो जाये लेकिन शहर को पहचान तो घंटाघर ही देते हैं।

जम्मू कश्मीर को मिलेगा पूर्ण राज्य का दर्जा, जल्द होंगे विधानसभा चुनाव' लोकसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी का ऐलान

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार (12 अप्रैल) को उधमपुर में प्रचार करने पहुंचे. इस दौरान पीएम मोदी कहा कि जम्मू कश्मीर को उसका राज्य का दर्जा वापस मिलेगा और वह समय दूर नहीं जब केंद्रशासित प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होंगे. उधमपुर से भारतीय जनता पार्टी ने केंद्रीय मंत्री जीतेंद्र सिंह को मैदान में उतारा है. पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि कांग्रेस की कमजोर सरकारों ने शाहपुर कंडी डैम को 10 साल तक लटकाए रखा. इसके चलते जम्मू के गांव सुख गए थे. कांग्रेस के दौर में हमारे हक का पानी जो रावी से निकलता था वह पाकिस्तान जा रहा था. लोग उनकी असलियत को जान गए हैं अब जम्मू कश्मीर में भ्रम का मायाजाल नहीं चल पा रहा है. उन्होंने कहा,₹10 सालों में हमने आतंकवादियों और भ्रष्टाचारियों पर शिकंजा कसा है और अब आने वाले 5 सालों में इस प्रदेश को विकास की नई ऊंचाई पर ले जाना है. पिछले 10 साल में जम्मू कश्मीर पूरी तरह से बदल चुका है. सबसे बड़ी बात जम्मू कश्मीर का मन बदला रहा है.₹ पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि अब जम्मू कश्मीर में स्कूल जलाए नहीं जाते, बनाए जाते हैं. उन्होंने कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस पर परिवारवाद का आरोप लगाया और कहा कि दोनों पार्टियां परिवारवादी हैं. पीएम ने अनुच्छेद 370 को लेकर कहा, ₹आपके आर्शीवाद से 370 के मलबे को जमीन में गाड़ दिया है. मैं कांग्रेस को 370 वापस लाने की चुनौती देता हूं. सत्ता के लिए जम्मू-कश्मीर में 370 की दीवार बनाई गई थी.₹ प्रधानमंत्री ने कहा कि यह चुनाव देश में एक मजबूत सरकार बनाने का चुनाव है. मजबूत सरकार चुनौती के बीच काम करके दिखाती है. आज गरीबों के पास मुफ्त राशन की गांरटी है. 10 साल पहले कश्मीर के गांव में बिजली पानी और सड़क तक नहीं थे. मोदी की गांरटी मतलब गांरटी पूरा होने की गांरटी. आज आपके आर्शीवाद से मोदी ने गांरटी पूरी कर दी. पीएम ने कहा कि आज आतंकवाद, अलगावाद, सीमा पार से गोलीबारी, पत्थरबाजी इस चुनाव के मुद्दे नहीं हैं. देश के चप्पे-चप्पे में एक ही गुंज सुनाई दे रही है, फिर एक बार मोदी सरकार!

अयोध्या में विदेशी कोरोना का खतरा!, हाई अलर्ट पर प्रशासन

परिवहन विशेष न्यूज

अयोध्या में रामनवमी को लेकर उत्सव की तैयारी है। पूरी अयोध्या रामनवमी को लेकर उत्साहित है। भगवान राम के भव्य मंदिर में विराजने के बाद यह पहली रामनवमी है। बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। इसी बीच विदेशों में बढ़ते कोरोना के मामले ने प्रशासन के कान खड़े कर दिए हैं। देश के बाहर से आने वाले भक्तों के लिए यहां के हॉस्पिटलों में विशेष तौर पर इंतजाम किए गए हैं। उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि बढ़ते हुए कोविड-19 के मामलों से बचने के लिए रोकथाम के सारे उपाय किए जा रहे हैं। विदेशी मेहमानों के लिए बनाये गए हैं 4 क्वारंटाइन वार्ड। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉ. अरुण प्रकाश श्रीवास्तव(Chief Medical Superintendent of District Hospital Dr. Arun Prakash Srivastava)ने बताया कि हमें कोविड-19 से निपटने के लिए हाई अलर्ट पर रखा गया है। सभी परिस्थितियों से निपटने के लिए हम बिलकुल तैयार हैं। इसीलिए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में 4 स्पेशल क्वारंटाइन वार्ड बनाया गया है। इसमें कोरोना संक्रमित विदेशी टूरिस्ट को रखा जाएगा। 17 अप्रैल को रामनवमी है। इस दौरान अगर किसी भी विदेशी भक्त में कोरोना के लक्षण पाए जाते हैं तो उन्हें क्वारंटाइन वार्ड में 14 दिन तक रहना होगा।

भारतीय सिनेमा और सियासत का सच, जब खुलीं परतें तो कुछ ने बटोरीं तालियां तो कुछ के हिस्से आई नफरत

लोकसभा चुनाव के बीच राजनीतिक पार्टियों के भ्रष्टाचार सत्ता के दुरुपयोग अव्यवस्था के मुद्दे छाए हुए हैं जिन-हें प्रमुखता से उठाने में हमेशा आगे रहा सिनेमा। फिर चाहे अयोध्या से लौटते कार सेवकों से भरी ट्रेन में आगजनी पर आधारित फिल्म साबरमती रिपोर्ट व इमरजेंसी में राजनीति की झलक नजर आए या फिर अतीत में भी राजनीति सरकार इंकलाब जैसी कई फिल्में बनीं। इन सबमें राजनीतिक दांव-पेंच को दिखाया गया।

परिवहन विशेष न्यूज

मुंबई। लोकसभा चुनाव में इन दिनों छाए हैं राजनीतिक पार्टियों के भ्रष्टाचार, सत्ता के दुरुपयोग, अव्यवस्था के मुद्दे, जिन्हें प्रमुखता से उठाने में हमेशा आगे रहा सिनेमा। अयोध्या से लौटते कार सेवकों से भरी ट्रेन में आगजनी पर आधारित फिल्म साबरमती रिपोर्ट व इमरजेंसी में भी है राजनीति की झलक। वहीं अतीत में भी राजनीति, सरकार, इंकलाब जैसी कई फिल्में बनीं, जिनमें दिखा राजनीतिक दांव-पेंच का चित्रण।

राजनीति फिल्म में राष्ट्रवादी पार्टी की आधिकारिक बैठक चल रही है, जिसमें चुनाव में पार्टी के उम्मीदवार को लेकर निर्णय लिया जाना है। अचानक पार्टी के नेता की गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर का बेटा सूरज (अजय देवगन) वहां पहुंचकर दलितों और पिछड़ों के वास्तविक प्रतिनिधि के तौर पर आजाद नगर सीट से चुनाव लड़ने के लिए पार्टी का टिकट मांगता है।

बैठक में मौजूद कुछ लोगों को उसका रवैया नागवार गुजरता है, पर उसके तीखे तेवर और नेतृत्व क्षमता को भांपकर मनोज बाजपेयी का पात्र उन्हें दलितों और पिछड़ों के नेता के तौर पर पार्टी में शामिल किए जाने का एलान कर देता है।

नाना पाटेकर, रणबीर कपूर, अर्जुन रामपाल और कैटरीना कैफ जैसे सितारों से सजी इस फिल्म में प्रकाश झा ने भारतीय राजनीति के दिग्गज राजनेताओं की

महत्वाकांक्षाओं और लक्ष्य साधने के लिए अपनाए जाने वाले दांव-पेंच का चित्रण किया था। राजनीति फिल्म के उक्त दृश्य से मिलता-जुलता परिदृश्य है इन दिनों देश व राजनीतिक दलों का। एक ओर जहां पार्टी का टिकट पाने की होड़ है, तो वहीं लोगों को आस है ऐसे जनप्रतिनिधि की जो उनकी आकांक्षाओं को सामने रख सके।

राजनीतिक पृष्ठभूमि से जुड़ी फिल्में राजनीति, आरक्षण और सत्याग्रह बना चुके प्रकाश झा कहते हैं, "मैं ऐसे सामाजिक और राजनीतिक विषयों पर फिल्में बनाता हूं, जो सार्वजनिक होते हैं। ऐसे विषयों को लेकर विचारधाराएं होंगी और वाद विवाद की संभावना भी रहेगी।

विवाद से बचने के लिए मैं या तो वह चीज कहूं ही नहीं, लेकिन यदि मुझे लगता है कि उस पर बात होनी चाहिए तो मैं कहता हूं। विवाद पैदा होने का डर भी रहता है, उसी वजह से संयमित रहता हूं। मैं किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन अपनी समझदारी से सच जरूर बोलूंगा।"

कल्पना व वास्तविकता में गुंथी कहानियां

राजनीतिक पृष्ठभूमि पर बनी कुछ कहानियां काल्पनिक रहीं तो कुछ वास्तविक घटनाओं या व्यक्तियों से प्रेरित होकर बनाई गईं। इनमें आंधी, किस्सा कुर्सी का, न्यू डेल्ही टाइम्स, नायक : द रियल हीरो, सरकार, राजनीति, आरक्षण, सत्याग्रह, रक्त चरित्र, इंदु सरकार, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, ठाकरे, द ताशकंद फाइल्स, द कश्मीर फाइल्स और आर्टिकल 370 आदि शामिल रही हैं।

फिल्मों में राजनीतिक पहलू दिखाने को लेकर फिल्मकार अली अब्बास जफर कहते हैं कि राजनीतिक घटनाक्रम वास्तविक हो सकते हैं, जिन्हें कुछ काल्पनिक या असल पात्रों के माध्यम से दर्शाया जा सकता है, पर कहानी का प्रभाव ऐसा होना चाहिए जो दर्शकों की संवेदनाओं से जुड़ सके।

फिल्म जोगी में हमने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद सिख विरोधी दंगों से जुड़ी मानवीय व्यथा को दर्शाया था। एक परिवार की आपबीती के माध्यम से हमने अपनी कहानी कही थी।

सत्य छूता है दिलों को

बहरहाल, हिंदी फिल्म उद्योग के लिए राजनीतिक घटनाक्रमों पर सफल फिल्में देना इतना सहज नहीं रहा है। अक्सर ऐसी फिल्मों को विवादों का सामना करना पड़ता है। फिल्मकार विवेक रंजन अग्निहोत्री की द ताशकंद फाइल्स जहां पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की रहस्यमय मौत के आसपास की घटनाओं पर आधारित थी, वहीं द कश्मीर फाइल्स में कश्मीरी पंडितों के पलायन की घटनाओं को उकेरा गया था। दोनों ही फिल्में चर्चा में रहीं।

विवेक पर फिल्मों के बहाने राजनीतिक दलों के हित साधक बनने के आरोप भी लगे, जिन्हें खारिज करते हुए विवेक ने कहा कि राजनीति से प्रेरित फिल्में आजतक सफल नहीं हुई हैं। वही फिल्में दर्शकों को भाती हैं, जिनकी कहानी उनकी संवेदनाओं को स्पर्श करती है। जब सत्य होता है तो लोग देखते हैं।

इन फिल्मों की बाक्स ऑफिस सफलता को लेकर फिल्म निर्माता और बिजनेस एक्सपर्ट गिरीश जौहर कहते हैं, ₹राजनीति एक वृहद विषय है, इससे जुड़े कई पहलुओं पर फिल्में बन सकती हैं।

इससे जुड़ी आर्टिकल 370 और द कश्मीर फाइल्स फिल्में सफल रहीं।

वास्तविक घटनाओं या व्यक्तियों से जुड़ी फिल्मों में फिल्मकार का एक नजरिया होता है। लोग उसे देखना चाहते हैं, उसके बारे में जानना चाहते हैं।

राजनेता की छवि

मुझे जो सही लगता है मैं करता हूं... वो चाहे भगवान के खिलाफ हो, समाज के खिलाफ हो, पुलिस, कानून... या फिर पूरे सिस्टम के खिलाफ क्यों ना हो...फिल्म सरकार में अमिताभ बच्चन के पात्र का यह संवाद कट्टर राजनेता की छवि को दिखाता है तो वहीं एक अन्य फिल्म इंकलाब में सत्ता विरोधी लहर को हवा देने के बाद जब स्वार्थी राजनेताओं द्वारा सरकार बनाने की बारी आती है तो नायक बने अमिताभ भरी बैठक में भ्रष्ट नेताओं को मौत के घाट उतार देते हैं।

फिल्म आज का एमएलए राम अवतार में नायक राजेश खन्ना जनता को उनके मत का मूल्य समझाते नजर आते हैं। दलगत राजनीति से परे फिल्मों के नायक पर्दे पर सच्चाई और नैतिकता के मूल्यों को सामने रखते हुए जब अन्याय का प्रतिकार करते दिखते हैं तो दर्शक भी झूम उठते हैं।

आपातकाल की पृष्ठभूमि में

मधुर भंडारकर की फिल्म इंदु सरकार आपातकाल की पृष्ठभूमि में गढ़ी गई काल्पनिक कहानी थी, वहीं कंगना रनौत की आगामी फिल्म इमरजेंसी में भी राजनीति का यह अहम घटना चक्र उठाया गया है।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक संजय कुमार बाटला द्वारा इम्प्रेशंस प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग लिमिटेड, सी-18,19,20 सेक्टर 59, नोएडा (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित एवं 3, प्रियदर्शनी अपार्टमेंट ए-4, पश्चिमी विहार, नई दिल्ली- 110063 से प्रकाशित। सम्पर्क : 9212122095, 9811902095 . newstransportvishesh@gmail.com
(इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी) किसी भी कानूनी विवाद की स्थिति में निपटारा दिल्ली के न्यायालय के अधीन होंगे। RNI No :- DELHIN/2023/86499. DCP Licensing Number F.2 (P-2) Press/2023